सत्यमेव जयते

ट्राईफेड TRIFED

tRIBES india ट्राइब्स इंडिया

VDY वन धन योजना

भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड

जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

ट्राईफेड का सफर – जनजातीय समुदाय के सभी मित्रों और भागीदारों के लिए एक रिपोर्ट

प्रधान मंत्री जी की दूरदर्शिता

"हम देश के जनजातीय क्षेत्रों में 50,000 'वन धन विकास केंद्र' स्थापित करेंगे ताकि वनोपजों के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो तथा जनजातीय समुदाय को रोजगार प्रदान किया जा सके और उनकी आय में वृद्धि हो सके।"

- संकल्प पत्र लोक सभा 2019 पृष्ठ 33, अनुभाग सुदृढ़ीकरण 'सबका विकास'

'वार्षिक प्रगति पर्याप्त नहीं है,
भारत को ऊंची छलांग की आवश्यकता है'

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी - अगस्त 15, 2019

प्रधान मंत्री ने दिल्ली में लाल किले के प्राचीर से स्वतंत्रता दिवस के अपने भाषण में ***देश की तरक्की और विकास को तेज करने की आवश्यकता पर बल दिया।***

जनजातीय समुदाय की अवस्था को सुधारने की संवैधानिक प्रतिबद्धता को पूरा करना

1993 में संविधान के 73वें और 74वें संशोधन, पंचायतों के प्रावधान (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, **1996 (पेसा)** और **वनाधिकार अधिनियम, 2006 (एफआरए)** का उद्देश्य वनों में रहने वाले जनजातीय समुदाय को विभिन्न विशेषाधिकारों के साथ सशक्त बनाना है, जिसमें लघु वनोपज एवं लघु खनिज शामिल हैं। **पेसा और एफआरए के उचित कार्यान्वयन से जनजातीय समुदाय को जीवन की गरिमा मिलेगी और सामाजिक एवं आर्थिक सुख हासिल करने में मदद मिलेगी।**

जनजातीय समुदाय के लिए आजीविका व रोजगार के अवसर

न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से लघु वनोपजों का विपणन और लघु वनोपजों के लिए मूल्य श्रृंखला का विकास

50 लाख से अधिक वनवासी संग्रहकर्ताओं को संग्रहण और मजबूत ब्रांडिंग व विपणन द्वारा समर्थित लाभकारी मूल्यवर्धन में संलग्न करना

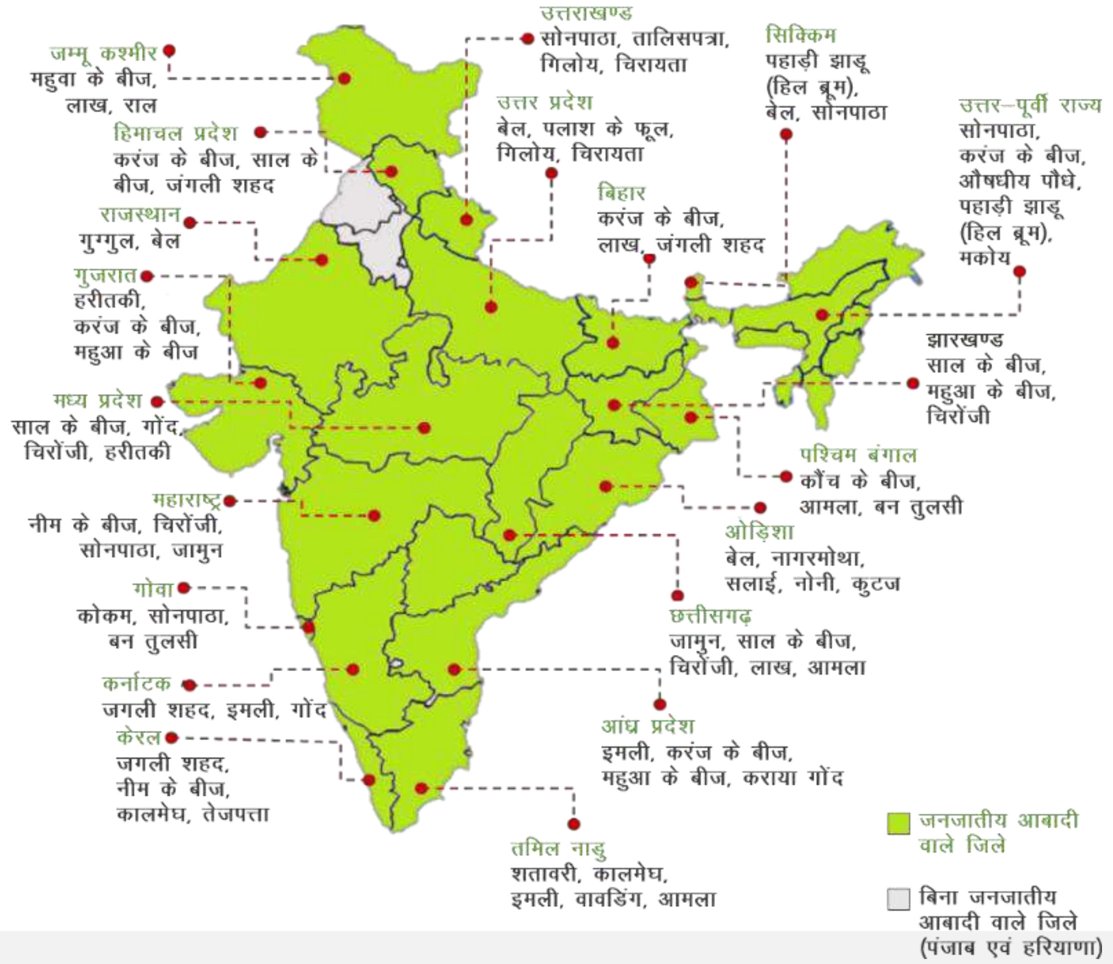

जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास एवं विपणन के लिए संस्थागत समर्थन

खरीद, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केटिंग के माध्यम से 5 लाख से अधिक कारीगरों को लाभकारी रोजगार में संलग्न करना

उचित दाम
हक से मांग!

लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य

लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

लोकार्पण 2013-14

- ✓ जनजातीय संग्रहकर्ताओं को उचित एवं लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना
- ✓ बाजार मूल्यों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से ऊपर बढ़ाने में सहायक
- ✓ लघु वनोपजों का राष्ट्र-व्यापी आच्छादन - वर्तमान में 87
- योजना के 2 घटक हैं
  - ➢ लघु वनोपजों की खरीद
  - ➢ बुनियादी ढांचा विकास - खरीद केंद्र
- लघु वनोपजों की खरीद
  - ➢ भारत सरकार की निधियों के माध्यम से खरीद
  - ➢ राज्य सरकार की निधियों के माध्यम से खरीद
  - ➢ निजी व्यापारियों द्वारा खरीद
- बुनियादी ढांचे का विकास
  - ➢ गोदाम @ 3.25 लाख
  - ➢ हाट बाजार का आधुनिकीकरण @ 5 लाख
  - ➢ सामान्य सुविधा शेड @ 8 लाख

जुलाई 2021

₹ **3,841 करोड़ से अधिक**
जनजातीय समुदाय को सीधे लाभ

55 लाख से अधिक लाभार्थी

₹ **321.21 करोड़**
भारत सरकार की निधियां

₹ **1521.82 करोड़**
राजकीय निधियां

₹ **2,000 करोड़ से अधिक**
निजी व्यापार

22 राज्यों मे कार्यान्वयन

लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की प्रगति

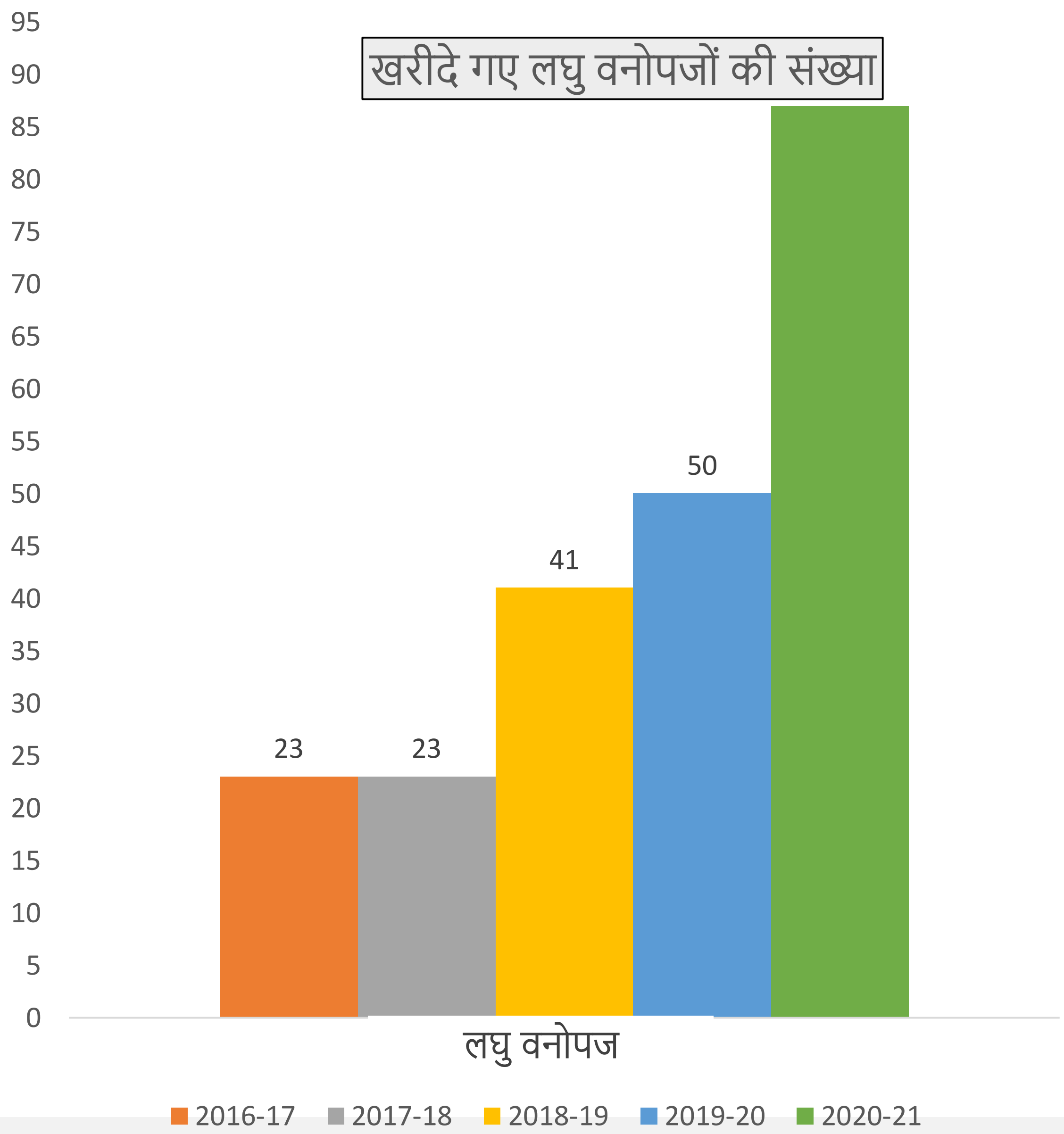

9 → 22
आच्छादित राज्य

1 → 25
लाभार्थी परिवार (लाख में)

खरीद केन्द्रों की कुल संख्या
6931

लघु वनोपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना की प्रगति

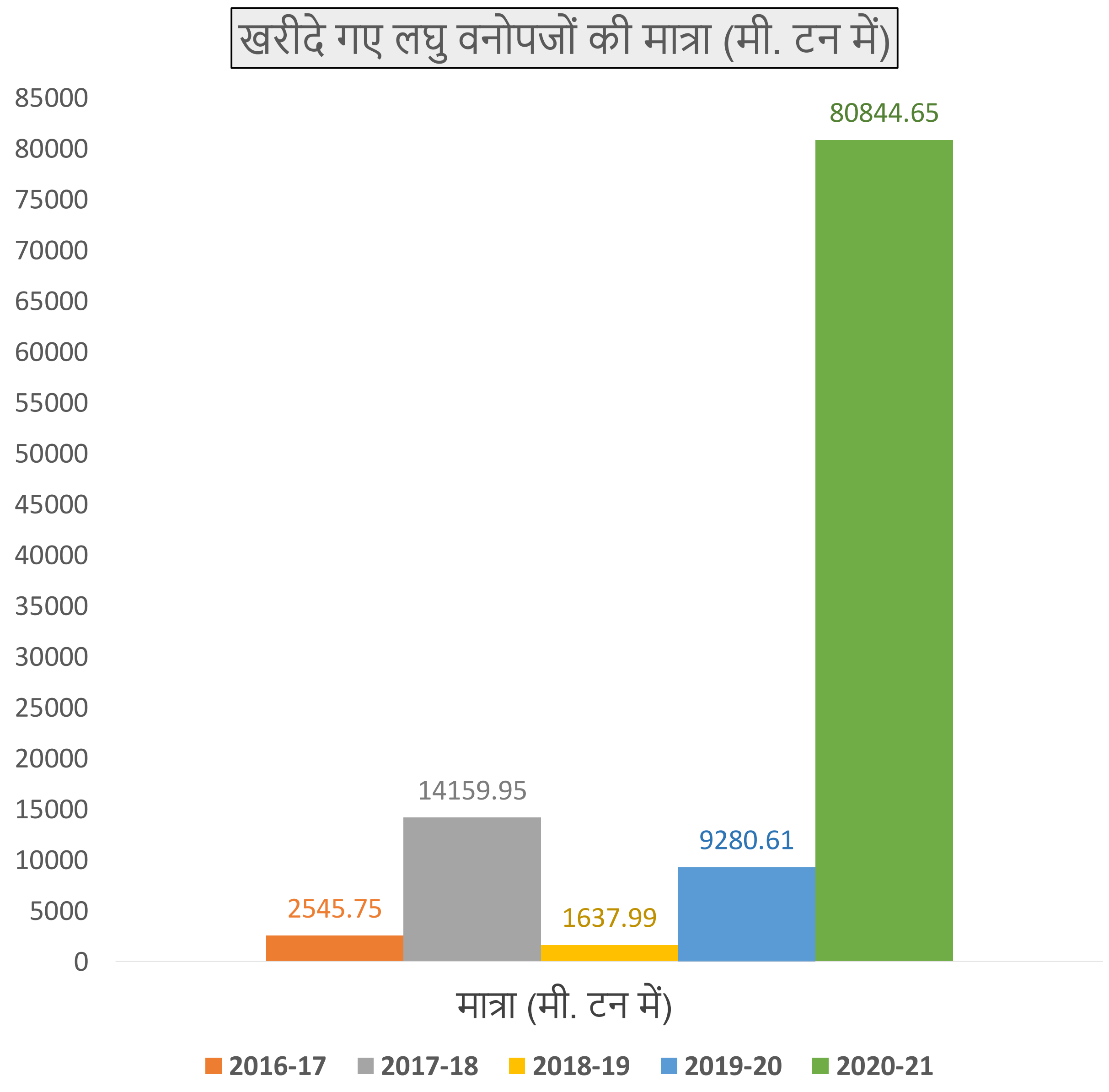

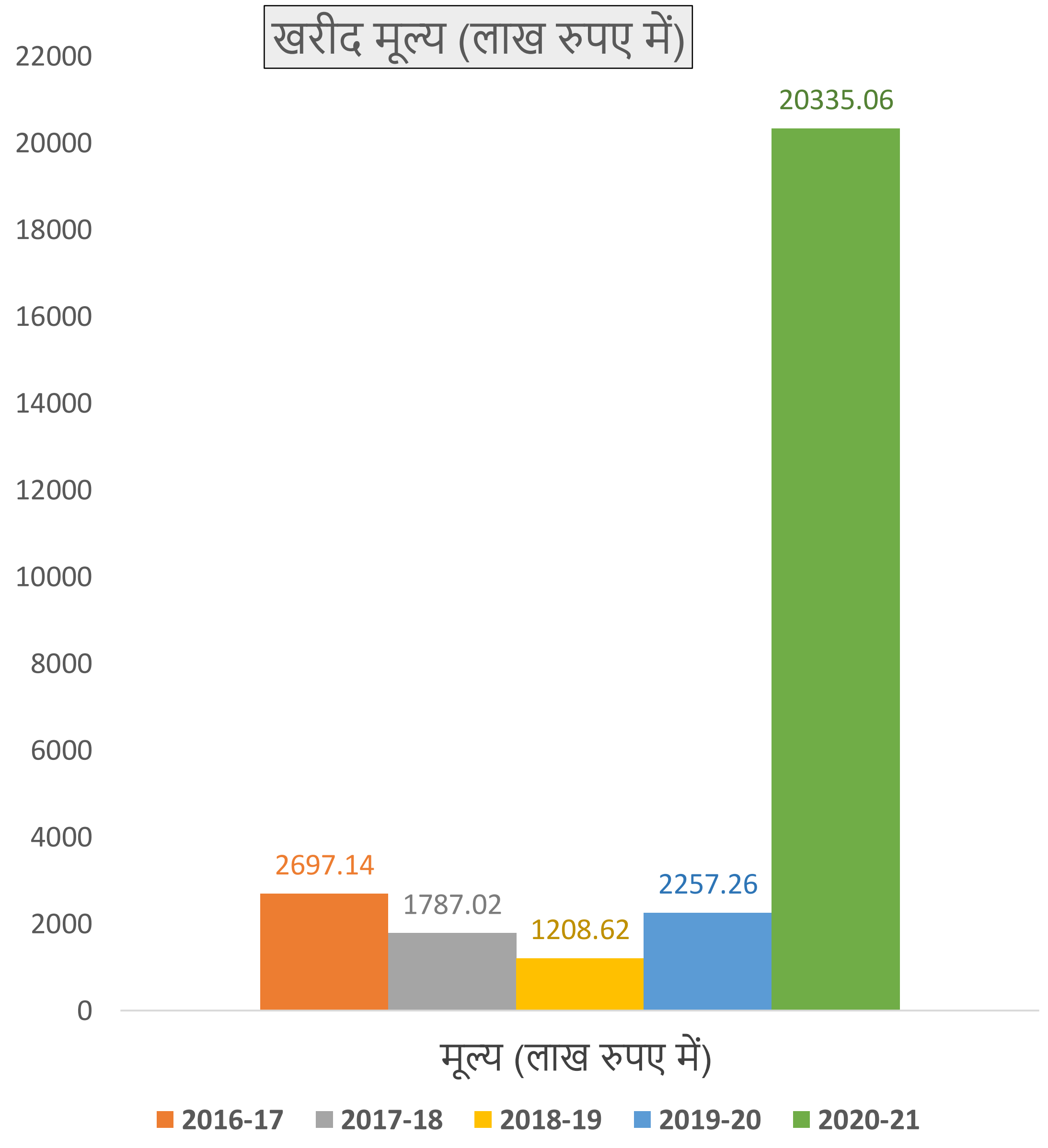

वन धन योजना

वन धन योजना

संरचना

- प्रत्येक वीडीएसएचजी - 20 सदस्य
- प्रत्येक वीडीवीके समूह (वीडीवीकेसी) - 15 वीडीएसएचजी - 300 सदस्य
- 60% जनजातीय सदस्य – अनिवार्य
- मजबूत प्रशासन तंत्र - राज्य नोडल विभाग, राज्य कार्यान्वयन एजेंसी, जिला कार्यान्वयन इकाइयां, परामर्श एजेंसियां

गतिविधियां

- प्रशिक्षण व उपकरण के लिए प्रत्येक वीडीवीके समूह को 15 लाख रुपए का केंद्रीय अनुदान प्रदान किया जाता है
- वीडीवीकेसी - मूल्यवर्धन, पैकेजिंग, विपणन और ब्रांडिंग के लिए जनजातीय स्टार्ट अप
- मोबाइल ऐप तथा जीआईएस के माध्यम से सभी जनजातीय लाभार्थियों, वीडीएसएचजी और वीडीवीकेसी का डिजिटलीकरण
- गुणवत्ता जांच के माध्यम से वीडीएसएचजी का पंजीयन; ट्राईफेड के 141 बिक्री केंद्र और ईकामर्स प्लेटफॉर्म ट्राइब्सइंडिया, अमेज़ॅन, पेटीएम, स्नैपडील, फ्लिपकार्ट के माध्यम से बिक्री

आच्छादन

25 राज्य;
253 जिले

6.77 लाख लाभार्थी

2,275 वीडीवीके समूह

37,904 वीडीएसएचजी

336.95 करोड़ निधियां स्वीकृत

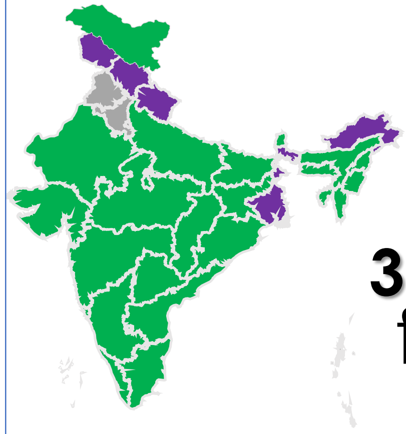

पश्चिम बंगाल,
हिमाचल प्रदेश,
जम्मू-कश्मीर –
अभी शुरू होना बाकी है
पंजाब और हरियाणा - शून्य

लक्ष्य

- **लक्ष्य** - 50,000 वीडीएसएचजी की स्थापना
- 10 लाख जनजातीय उद्यमियों को लाभ
- **समय रेखा** - जुलाई 2021 का अंत
- **आगे का सफर** - 800 वीडीवीके समूहों की स्वीकृति और संचालन

मूल्यवर्धन और अभिसरण के माध्यम से आय सृजन

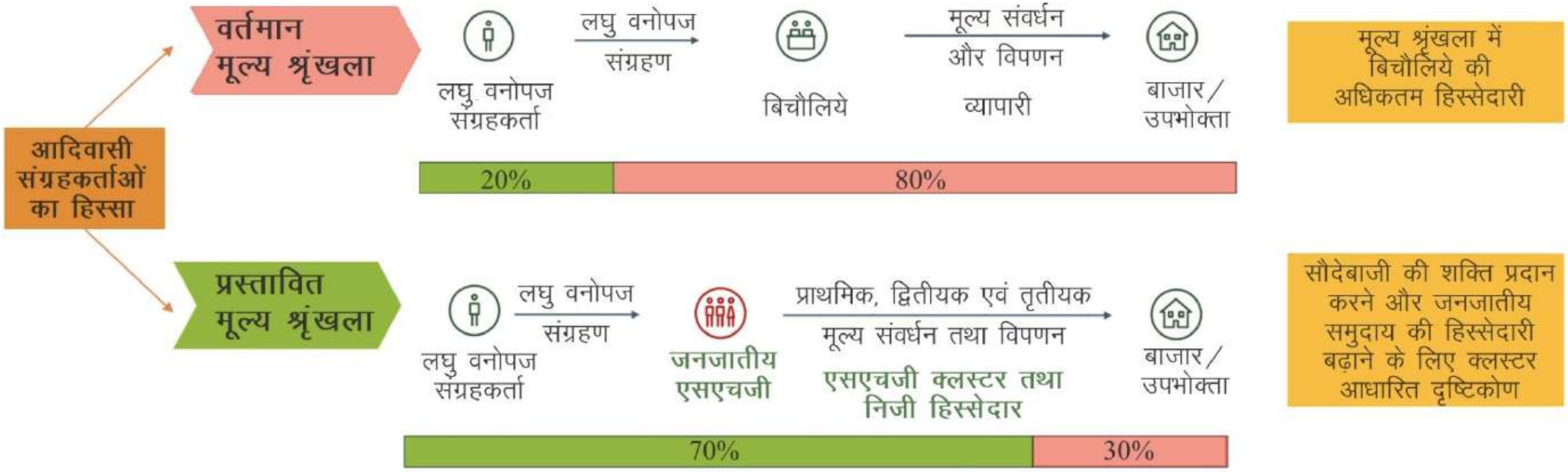

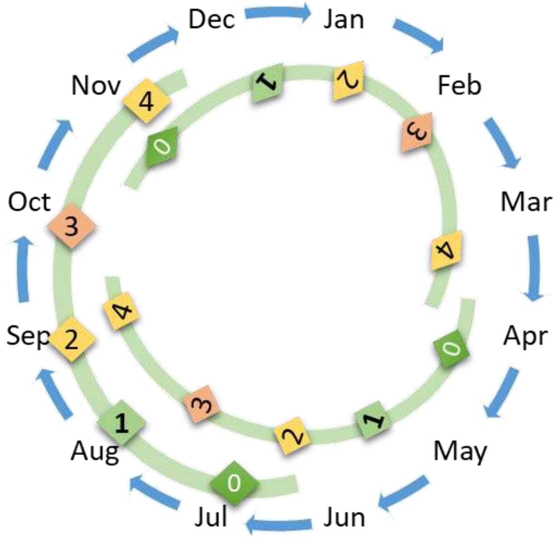

जनजातीय परिवारों के लिए पूरे वर्ष सतत आय

- लघु वनोपजों के संग्रहण और बिक्री का जनजातीय वार्षिक आय में 40 - 60% का योगदान है
- मूल्य संवर्धन उनकी आय को तीन से चार गुना करने में मदद करता है
- अभिसरण कार्यक्रम (कृषि/फूलों की खेती/औषधीय पौधों की खेती/अन्य गतिविधियां उन्हें पूरे वर्ष आय अर्जित करने का अवसर प्रदान करेंगे)

वन धन योजना – मिशन काल से अब तक की प्रगति

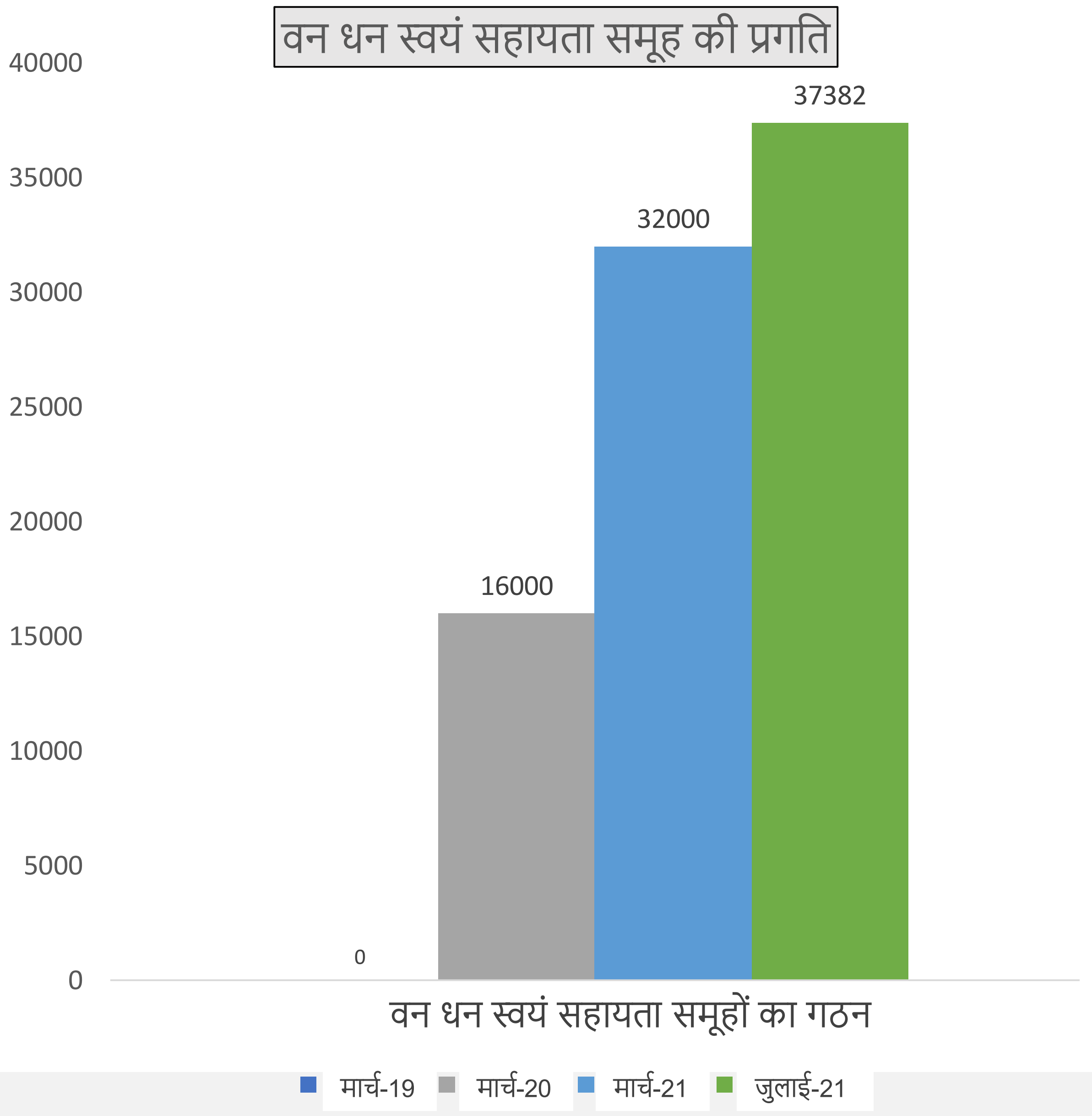

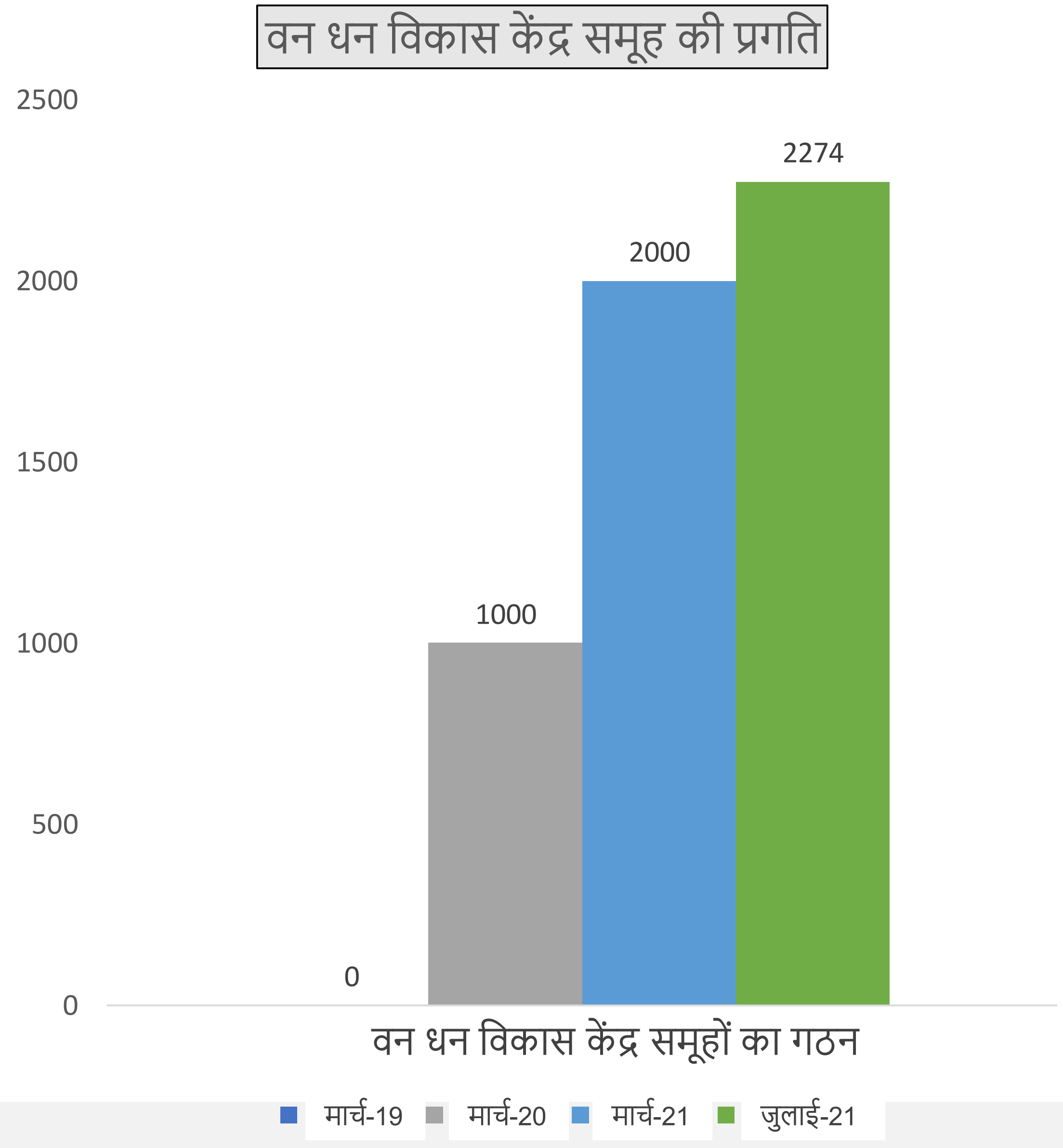

वन धन की झलक

जवाधु, जमुनामराथुर और कूट्टाथुर

तिरुवन्नामलाई, तमिलनाडु

	अप्रसंस्कृत माल का बिक्री मूल्य (एमएसपी)	मूल्य वर्धित माल का बिक्री मूल्य
शहद	रु. 225 प्रति किलोग्राम	रु. 800 प्रति किलोग्राम
छोटा-मोटा अनाज	रु. 40-80 प्रति किलोग्राम	रु. 200-1200 प्रति किलोग्राम
इमली	रु. 36 प्रति किलोग्राम	रु. 200-400 प्रति किलोग्राम

राज्य नोडल विभाग

जनजातीय कल्याण विभाग

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

सेलम, वेल्लोर तथा तिरुवन्नामलाई जिलों के जिला कलेक्टर

अप्रसंस्कृत माल –
छोटे-मोटे अनाज, शहद, इमली

मूल्य संवर्धन –
लघु वनोपजों का प्रसंस्करण व पैकेजिंग

तैयार उत्पाद –
छोटे मोटे अनाज, शहद, इमली

3 समूहों ने एक साथ मिलकर एक खाद्य प्रसंस्करण संस्था बनाई है और अब तक लगभग 12 लाख रुपए की बिक्री अर्जित की है

आदिवासी एकात्मिक सामाजिक संस्था
शाहपुर, ठाणे, महाराष्ट्र

कातकरी समुदाय

राज्य नोडल विभाग

जनजातीय कल्याण विभाग

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडल मर्यादित

अप्रसंस्कृत माल – गिलोय

मूल्य संवर्धन – गिलोय

तैयार उत्पाद

वीडीवीकेसी द्वारा कच्ची गिलोय को डाबर, बैद्यनाथ, हिमालय, विठोबा, शरणधर, भूमि प्राकृतिक उत्पाद केरल, त्रिविक्रम, मैत्री फूड्स आदि प्रमुख कंपनियों को बेचा गया है

1,57,00,000 रुपये मूल्य का ऑर्डर

पिछले डेढ़ साल में, समूह ने 12,40,000 रुपए के गिलोय पाउडर और 6,10,000 रुपए के सूखे गिलोय की बिक्री की है।

बोरबोरी
बक्सा, असम

	अप्रसंस्कृत माल का बिक्री मूल्य (एमएसपी)	मूल्य वर्धित माल का बिक्री मूल्य
शहद	रु. 225 प्रति किलोग्राम	रु. 700 प्रति किलोग्राम

राज्य नोडल विभाग

मैदानी जनजातियाँ और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग (डब्ल्यूपीटी एंड बीसी)

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

असम मैदानी जनजातीय विकास निगम लिमिटेड (एपीटीडीसी)

अप्रसंस्कृत माल – जंगली शहद

मूल्य संवर्धन – शहद का प्रसंस्करण तथा छनाई

तैयार उत्पाद – जंगली शहद

समूह में उत्पादित और पैक किए गए शहद का विपणन IIE द्वारा 'TRISSAM' ब्रांड के तहत किया जाता है।
समूह ने लगभग 1.5 लाख रुपए की बिक्री अर्जित की है और 300 जनजातीय स्वयं सहायता समूह संग्रहकर्ताओं को लाभान्वित किया है

मोरस
सिरोही, राजस्थान

	अप्रसंस्कृत माल का बिक्री मूल्य (एमएसपी)	मूल्य वर्धित माल का बिक्री मूल्य
दाल	रु. 20-100 प्रति किलोग्राम	रु. 100-800 प्रति किलोग्राम
छोटा-मोटा अनाज	रु. 40-80 प्रति किलोग्राम	रु. 200-1200 प्रति किलोग्राम
मिर्च	रु. 20 प्रति किलोग्राम	रु. 300-450 प्रति किलोग्राम

राज्य नोडल विभाग

जनजातीय क्षेत्र कल्याण विभाग

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी

राजस्थान जनजातीय क्षेत्र विकास सहकारी संघ लिमिटेड (राजसंग)

अप्रसंस्कृत माल / क्लस्टर केंद्र – दाल, बाजरा, गेहूं, मिर्च, मसाले, शहद

मूल्य संवर्धन – प्रसंस्करण व पैकेजिंग

तैयार उत्पाद – दाल, बाजरा, गेहूं, मिर्च, मसाले, शहद, अचार, पाउडर

समूह ने वर्तमान में ट्राइब्स इंडिया और स्थानीय स्तर पर उत्पादों की बिक्री के माध्यम से 0.88 लाख रुपए की बिक्री अर्जित की है वौर 300 जनजातीय परिवारों को लाभान्वित किया है

मिशन वन धन

ट्राईफेड, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार

संकल्प से सिद्धि

जनजातीय अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए प्रधान मंत्री की दूरदर्शिता का उपार्जन

VDY वन धन योजना

"मेरा वन, मेरा धन, मेरा उद्यम"

ट्राईफेड का मिशन

मिशन वन धन - उद्देश्य और गतिविधियां

मिशन वन धन के उद्देश्य

- स्थानीय स्तर पर उपलब्ध जनजातीय उत्पादों जिसमें लघु वनोपाज़/कृषि/फूलों की खेती/बागवानी/ औषधीय व सुगंधित पौधे तथा अन्य गतिविधियां शामिल हैं, के मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग और विपणन के माध्यम से जनजातीय समुदाय के लिए पूरे साल आय पैदा करने के अवसर **सुनिश्चित करना**

- बिना अधिकार वाली भूमि/मकान पर कब्जा जैसी विकट समस्याएं; लघु वनोपज संग्रहण पर प्रतिबंध; बिचौलियों द्वारा शोषण; विस्थापन, वन ग्रामों में विकास का अभाव आदि समस्यों का **समाधान करना**

मिशन वन धन की गतिविधियां

खुदरा एवं वितरण
- खुदरा बुनियादी ढांचा
- पहुँच गतिविधियाँ और कार्यक्रम

लघु वनोपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य
- वर्तमान में 87 लघु वनोपज
- खरीद - भारत सरकार की निधियां, केंद्रीय निधि और निजी व्यापार

मूल्य संवर्धन - अभिसरण
- ग्रामीण विकास मंत्रालय,
- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
- एमएसएमई
- कृषि मंत्रालय, आयुष
- ट्राइफूड पार्क: जनजातीय काय मंत्रालय (275(1) निधि)

वन धन योजना
- 15 लाख - वीडीवीकेसी अनुदान
- प्रशासन तंत्र

अन्य गतिविधियां – शोध एवं विकास, सूचना प्रौद्योगिकी के साथ रखरखाव/ एकीकरण, निगरानी तथा मूल्यांकन

मिशन वन धन – पहुँच लक्ष्य और विकास लक्ष्य

पहुँच लक्ष्य

लाभ - 1 करोड़ जनजातीय परिवार

रोजगार - 9 लाख जनजातीय परिवार

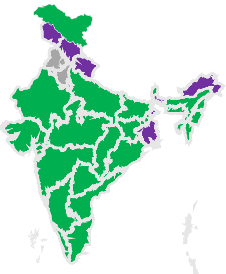

राज्य - जनजातीय आबादी वाले 27 राज्य

जिले - 308 जनजातीय बहुल जिले

विकास लक्ष्य

- लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना - बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से कार्यान्वयन सहायता
  - 300 हाट बाजार
  - 600 गोदाम
- 50,000 वन धन स्वयं सहायता समूहों (वीडीएसएचजी) की स्थापना
- 200 मिनी ट्राईफूड इकाइयों और 100 सार्वजनिक सुविधा केंद्रों की स्थापना
- डीएमएफ और अनुच्छेद 275(1) निधियों का उपयोग करते हुए 100 ट्राईफूड पार्कों की स्थापना
- 100 अलंकरण (स्फूर्ति) समूहों का विकास
- 200 ट्राइब्स इंडिया खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना
- ट्राईफूड और ट्राइब्स इंडिया ब्रांडों के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म की स्थापना
- किफायत हासिल करने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग

ट्राईफूड विकास की स्थिति

योजना का अवलोकन

ट्राईफूड - ट्राईफेड (जनजातीय कार्य मंत्रालय) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। यह लघु वनोपजों (एमएफपी) के लिए तृतीयक मूल्य संवर्धन केंद्र है जिसका उद्देश्य स्थानीय रोजगार सृजित करना और जनजातीय समुदायों के लिए उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करना है।

प्रमुख उद्देश्य : लघु वनोपजों (एमएफपी) के मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की **बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज बनाने की योजना** के तहत समर्थित

पीपीपी आधार पर निजी स्वामित्व वाली खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के साथ साझेदारी

जनजातीय समुदाय के लिए **रोजगार के अवसर पैदा करना** (आजीविका सृजन) और **उद्यमशीलता के अवसर प्रदान करना** (फॉरवर्ड लिंकेज)

कुल **कच्चे माल का 60%** आसपास के क्षेत्रों में पहचाने गए वीडीएसएचजी, वीडीवीकेसी से स्थानीय रूप से प्राप्त किया जाना है

ट्राईफूड – लघु वनोपजों के तृतीयक मूल्यवर्धन के लिए दो इकाइयों की स्थापना

25,000 जनजातीय संग्रहकर्ता लाभान्वित होंगे (जगदलपुर, छत्तीसगढ़ में 15,000 और रायगढ़, महाराष्ट्र में 10,000)

Government of India MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

ट्राईफेड TRIFED

MOFPI Ministry of Food Processing Industries Government of India

National Scheduled Tribes Finance and Development Corporation (NSTFDC)

संयुक्त पहल

- खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय,
- जनजातीय कार्य मंत्रालय और
- ट्राईफेड

11 करोड़ रुपे का निवेश

संसाधित की जाने वाली वस्तुएं

- महुआ, आंवला, जामुन, शरीफा, काजू, इमली, अदरक, लहसुन और अन्य फल एवं सब्जियां

ट्राईफूड जगदलपुर तथा रायगढ़ – प्रगति

जगदलपुर

रायगढ़

R&D तथा H&IG गतिविधियां

शोध एवं विकास (R&D) गतिविधियां

वीडीवीकेसी के साथ शोध प्रौद्योगिकियों को जोड़ना

डीएफओ, कांकेर के सहयोग से कांकेर जिले में 6 वीडीवीकेसी

डीएम, चिंतूर के समर्थन से चिंतूर जिले में वीडीवीकेसी

बीआईटी मेसरा द्वारा विकसित

कोल्ड क्रीम

शेविंग क्रीम

लिक्विड सोप

आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित

डीग्रीसिंग सफाई फॉर्मूलेशन

एसआरआईआईआर दिल्ली द्वारा विकसित

महुआ इमली कैंडी

तम रस

हर्बल हैयर डाई

चटनी / अचार

H&IG गतिविधियां

वर्ष 2020-21 के लिए कुल 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से 3 डीडब्ल्यूटी प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हो चुके हैं।

क्रम संख्या	राज्य	शिल्प	प्रशिक्षण का प्रकार
1.	कर्नाटक	केले का रेशा	सीटीपी
2.	कर्नाटक	बीदरी का काम	सीटीपी
3.	कर्नाटक	बेंत तथा बांस	
4.	कर्नाटक	टोडा कशीदाकारी	सीटीपी
5.	मध्य प्रदेश	परिधान निर्माण	
6.	पश्चिम बंगाल	बेंत तथा बांस	डीडब्लूटी
7.	गुजरात	हाथ की कशीदाकारी	डीडब्लूटी
8.	गुजरात	मनके व सजावट का काम	डीडब्लूटी
9.	गुजरात	सजावटी काम	डीडब्लूटी
10.	उत्तर प्रदेश	बनारसी सिल्क	डीडब्लूटी
11.	उत्तराखंड	ऊनी व जूट शिल्प	डीडब्लूटी
12.	तेलंगाना	सुई की कशीदाकारी	डीडब्लूटी
13.	राजस्थान	ब्लू पौटरी	डीडब्लूटी
14.	राजस्थान	ब्लॉक से छपाई	डीडब्लूटी

खुदरा तथा विपणन

खुदरा तथा विपणन

1709 लाख
2020-21 में खरीदे गए जनजातीय उत्पादों का मूल्य

RETAIL OUTLETS

141
पूरे भारत में खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या

2800+
पैनल में शामिल जनजातीय आपूर्तिकताओं की संख्या

29.63 करोड़
202-21 में अर्जित बिक्री

आदि महोत्सव – फ़रवरी-2021

- 1000+ जनजातीय कारीगर
- 3.8 करोड़ रुपए की बिक्री
- आगंतुकों की संख्या - 3.5 लाख

न्यूयार्क में ट्राइब्स इंडिया

- कार्यक्रम - अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस
- स्थान – न्यूयार्क
- 21 जून 2021

पिछले 5 वर्ष में प्रगति

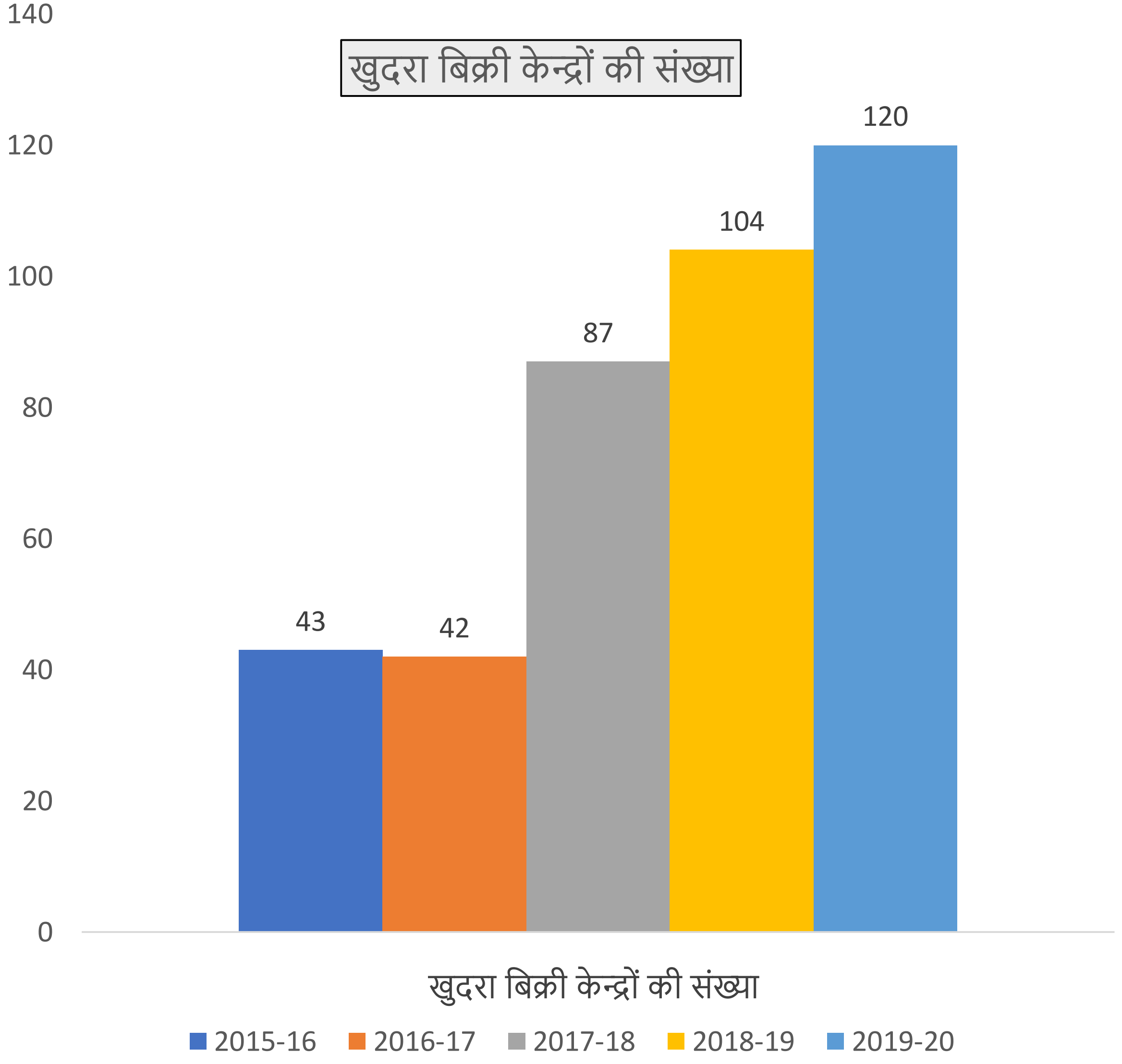

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, हालाँकि TRIBES India बिक्री केन्द्रों की संख्या बढ़कर 130 हो गई है

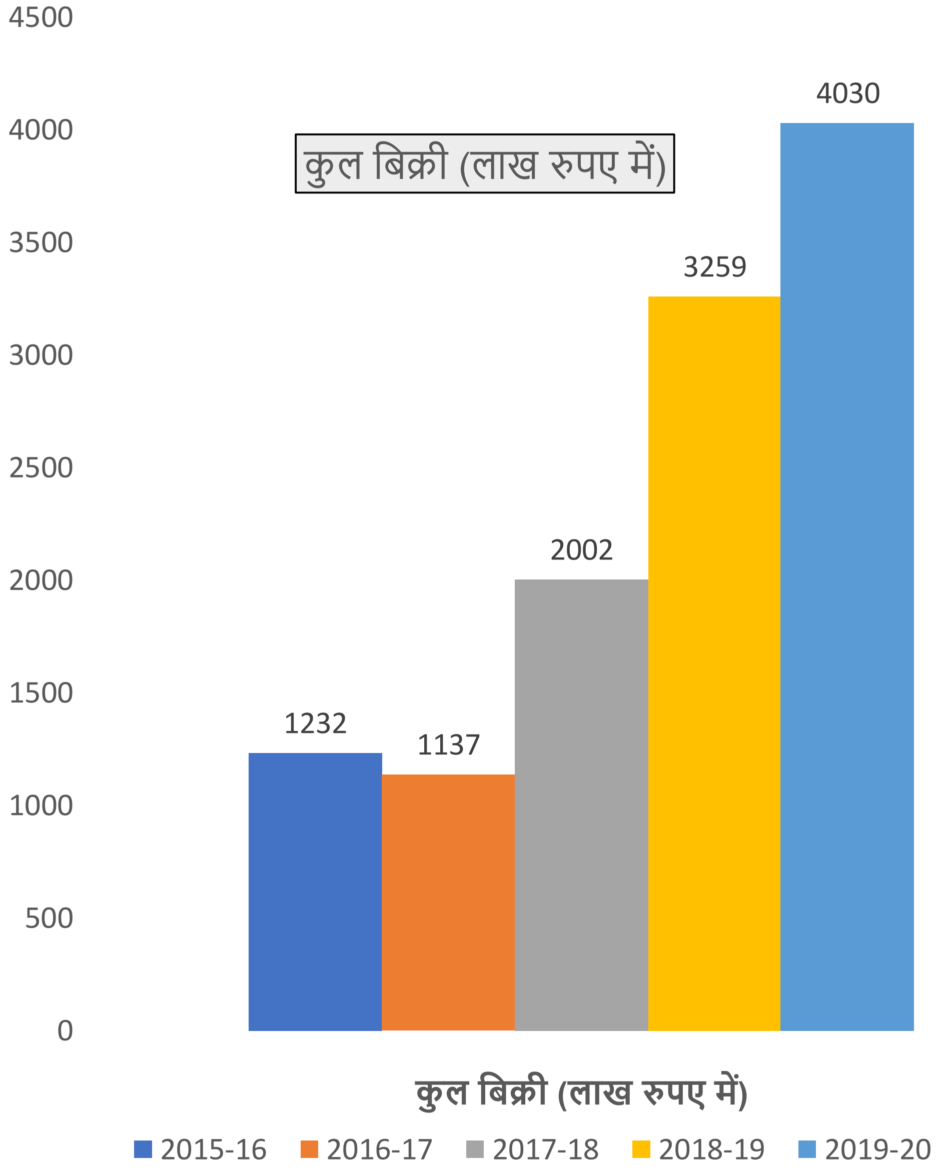

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, हालाँकि कुल बिक्री बढ़कर 29.63 करोड़ रुपए हो गई है

पिछले 5 वर्ष में प्रगति

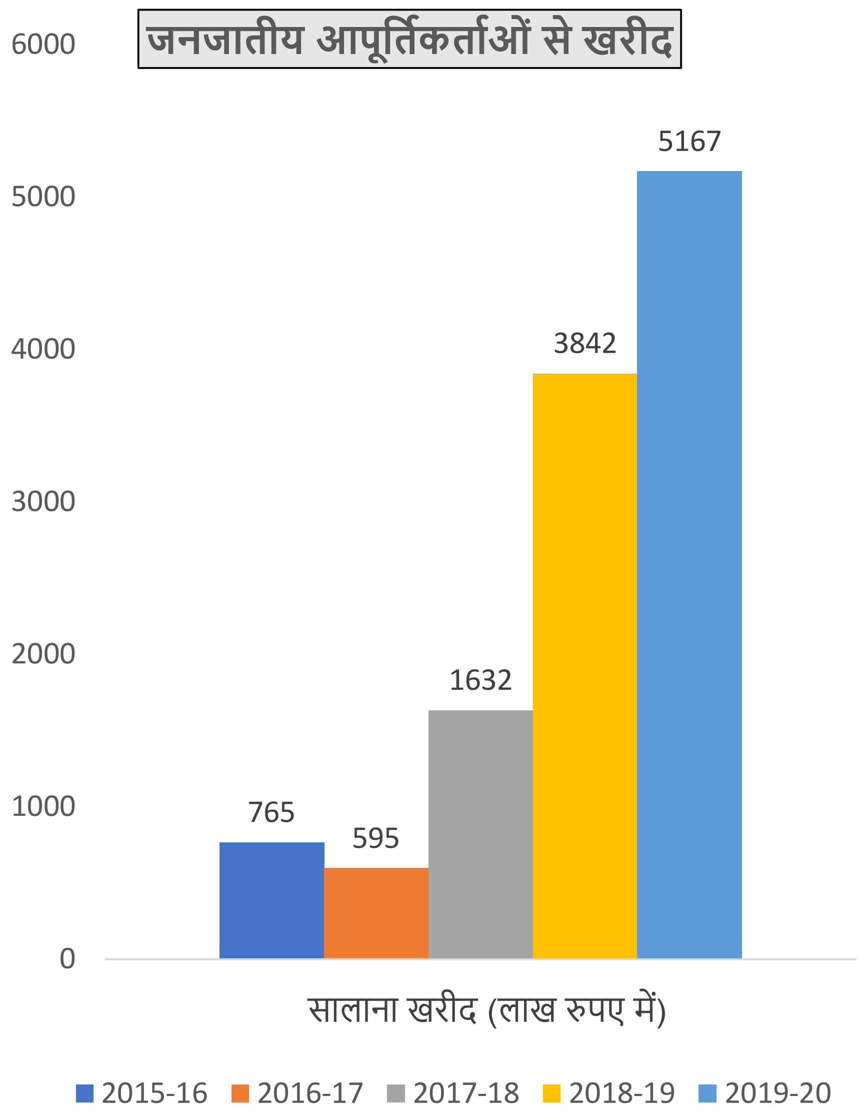

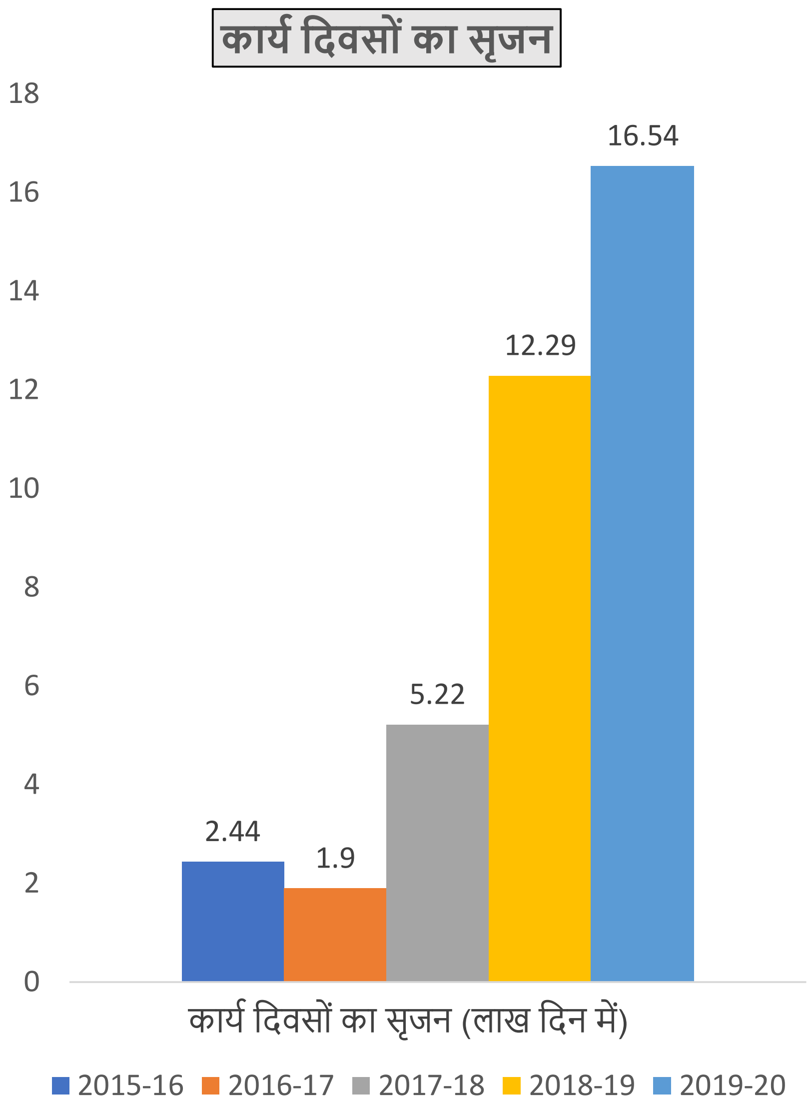

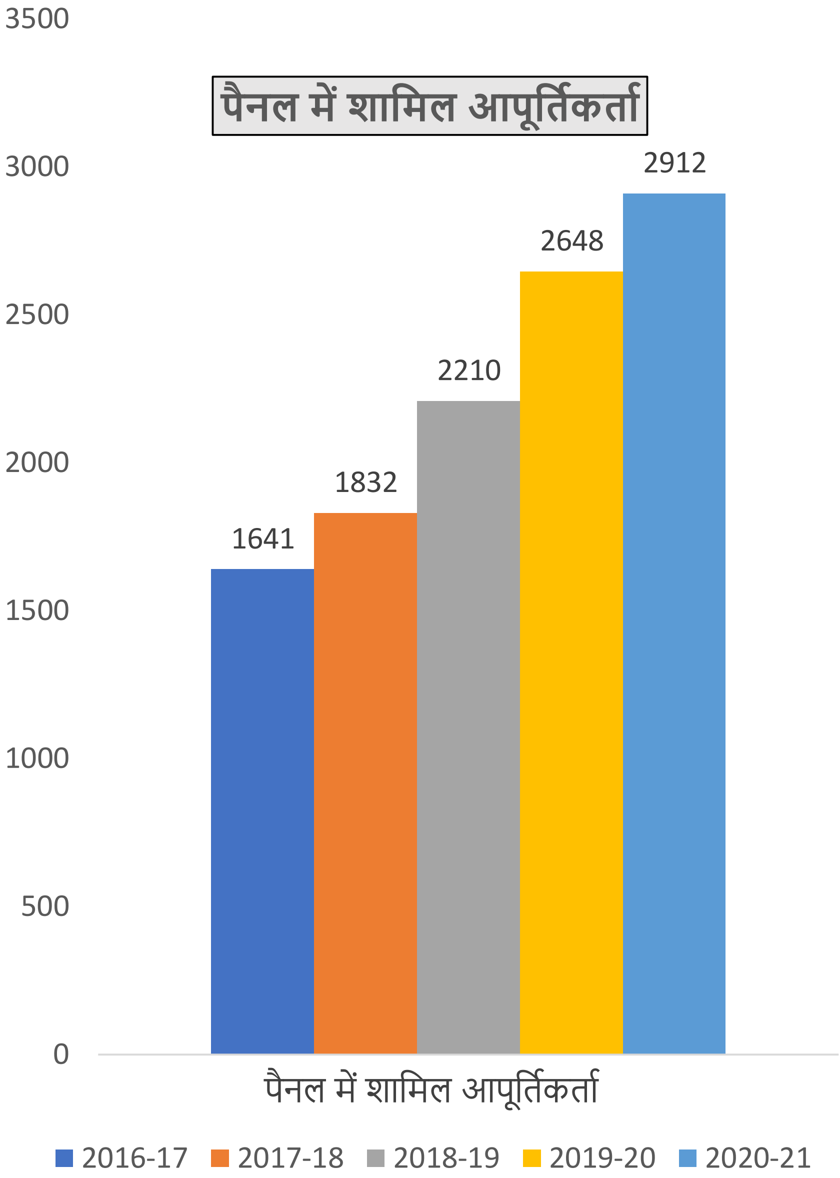

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, हालाँकि जनजातीय उत्पादों की कुल खरीद बढ़कर 17.09 करोड़ रुपए हो गई है

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, हालाँकि 5.47 लाख **कार्य दिवसों का सृजन हुआ** है

आदि महोत्सव

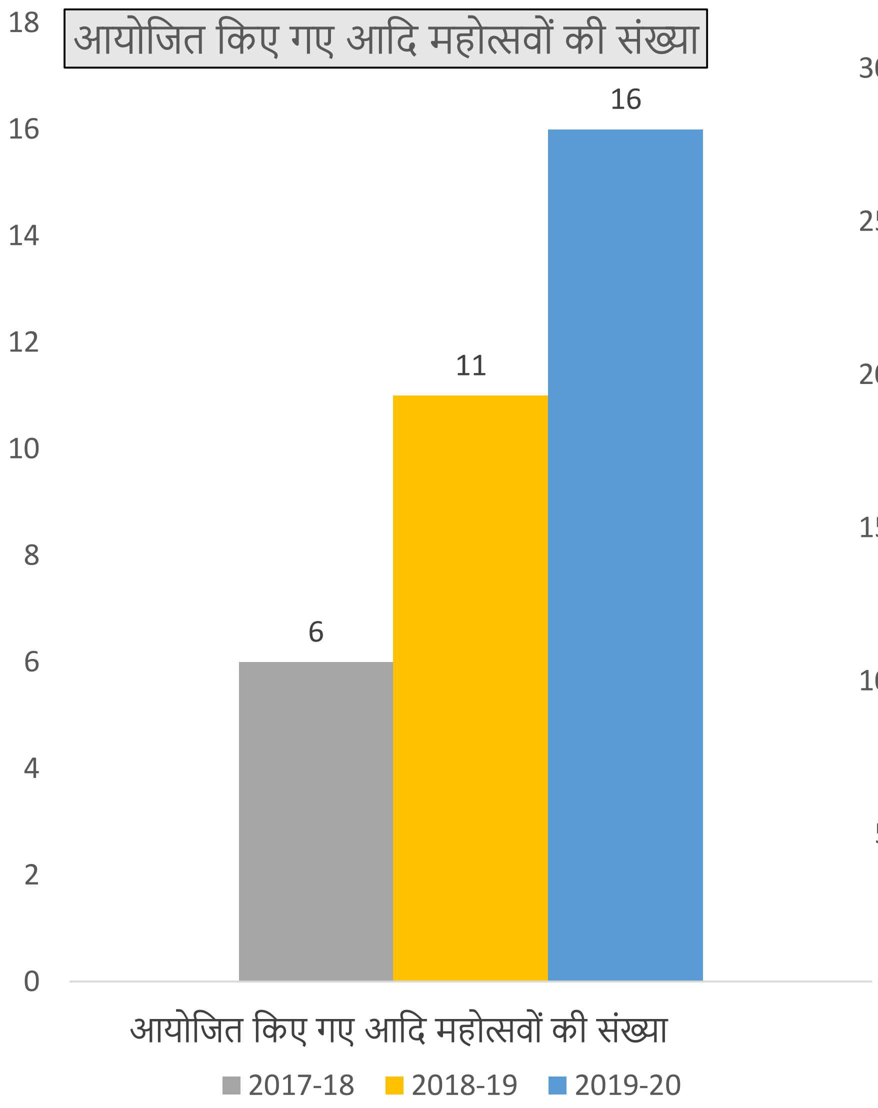

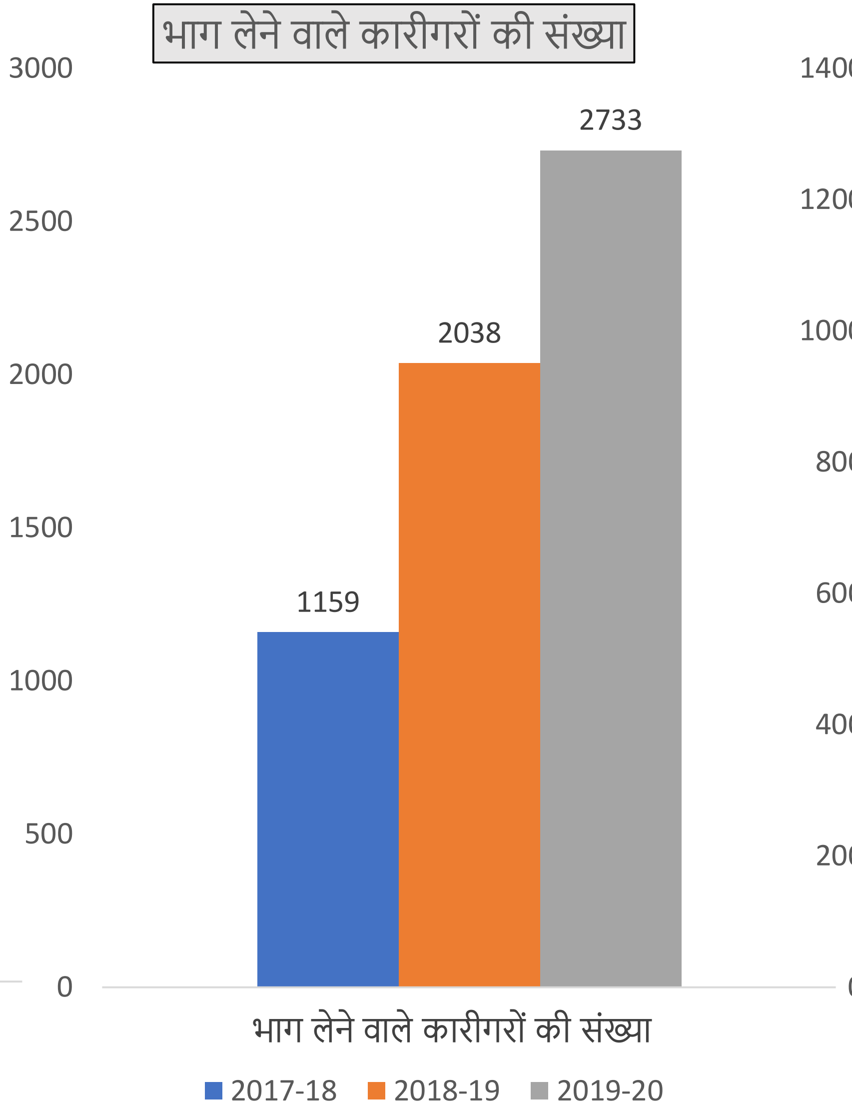

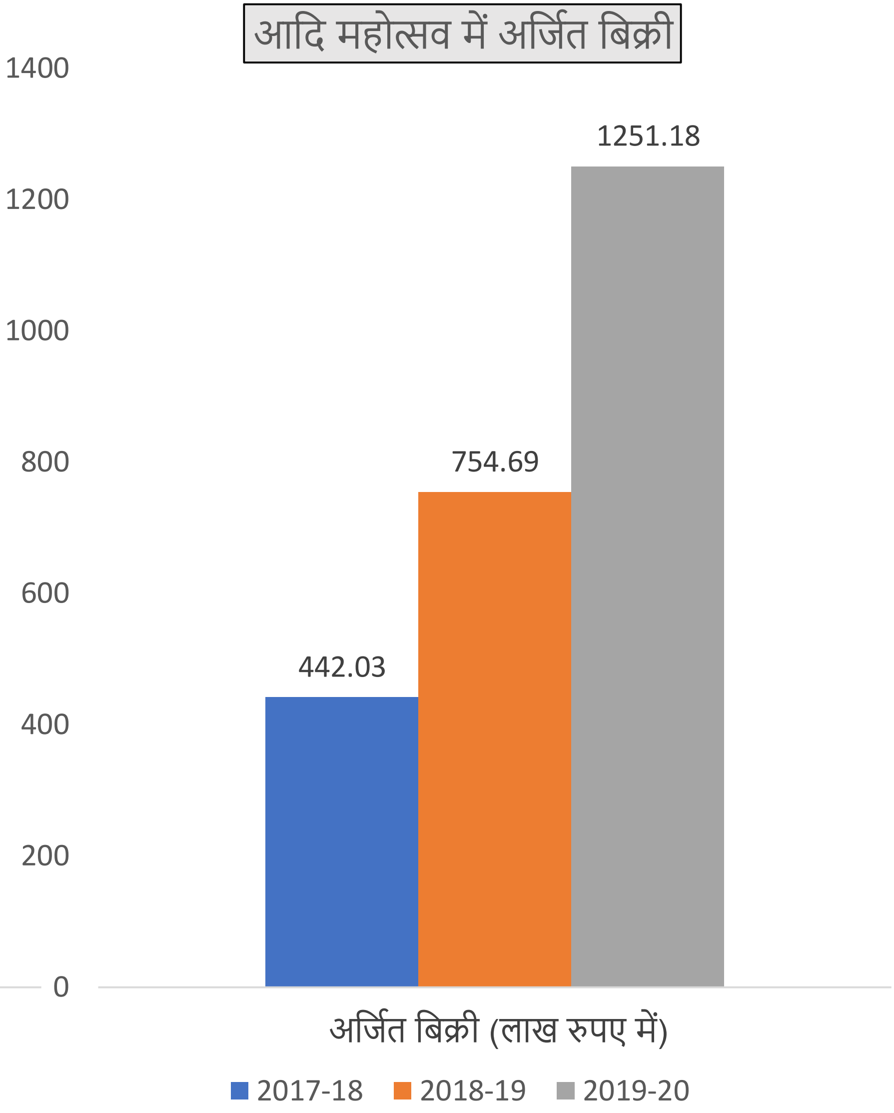

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, फिर भी दिल्ली हाट में एक आदि महोत्सव आयोजित किया गया था

*वर्ष 2020-21 एक COVID वर्ष है और इसलिए इसे मानकीकृत नहीं किया जा सकता है, फिर भी आदि महोत्सव में 390 लाख रुपए की बिक्री अर्जित की गई

भौगोलिक रूप से अनुक्रमित उत्पादों को बढ़ावा देना

ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों और ईकामर्स पोर्टल्स पर जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना

- 141 ट्राइब्सइंडिया बिक्री केंद्र
- tribsindia.com ई-कॉमर्स वेबसाइट व मोबाइल ऐप्स
- अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील अन्य

हमारे देश में भौगोलिक रूप से अनुक्रमित उत्पादों पर जागरूकता बढ़ाना

- जीआई उत्पादों में संलग्न सभी जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं में आईईसी
- जीआई उत्पादों के लिए अधिक जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं को प्रोत्साहित करना और सूचीबद्ध करना

नए पंजीकरण के लिए उत्पादों को खोजने और पहचानने में सहायता करना

- ट्राईफेड वन धन योजना की राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों और ट्राईफेड के 14 क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से जीआई पंजीकरण के लिए संभावित जनजातीय उत्पादों की पहचान के लिए अभियान

पूर्वोत्तर क्षेत्र के जनजातीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए विपणन एवं रसद विकास

योजना के उद्देश्य

- **4,000 कारीगरों** की पहचान कर उन्हें सूचीबद्ध करना
- नए भौगोलिक संकेतों को पहचान कर उन्हें पंजीकृत करना और क्षेत्र से मौजूदा भौगोलिक संकेतों को बढ़ावा देना
- पूर्वोत्तर राज्यों के हस्तशिल्प व हथकरघा उत्पादों को बड़े पैमाने पर मुख्यधारा से जोड़ें
- पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदाय की आय में वृद्धि करना और उनके लिए साल भर आजीविका की सुविधा प्रदान करना
- पूर्वोत्तर की जनजातीय कलाकृतियों के लिए राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंच को सुगम बनाना

योजना के परिणाम

- बाजार के विकास के लिए 4000 कारीगरों को शामिल करना
- पूर्वोत्तर राज्यों के जनजातीय उद्यमों से लगभग 186 करोड़ रुपए मूल्य का संचयी कारोबार
- नए भौगोलिक संकेतकों की पहचान और उनका पंजीकरण
- जीआई टैग किए गए आइटम/उत्पादों के पैनल में शामिल विक्रेताओं/कारीगरों का अधिकृत उपयोगकर्ताओं के रूप में पंजीकरण
- पूर्वोत्तर के जनजातीय समुदाय के लिए एक ब्रांड तैयार करना

परियोजना की अवधि = 2 वर्ष

अभिसरण भागीदार

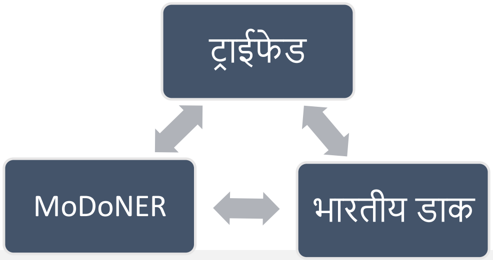

योजना का प्रस्तावित बजट = 150 करोड़ रुपए

अभिसरण

लघु वनोपज की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना तथा और ट्राईफूड के तहत अभिसरण

Ministry of MSME, Govt. of India

स्फूर्ति योजना के तहत **MSME-SFURTI** क्लस्टर व **ESDP** कार्यक्रम के तहत कौशल विकास

MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES GOVERNMENT OF INDIA

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - PM-FME योजना के तहत मिनी-ट्राईफूड परियोजनाएं

Government of India MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

जनजातीय कार्य मंत्रालय - **जनजातीय कार्य मंत्रालय** द्वारा अनुच्छेद 275 (i) के तहत जारी धन का उपयोग करते हुए **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय** और **एनएसटीएफडीसी** के सहयोग से **2 ट्राईफूड पार्क**

Ministry of Rural Development Government of India

ग्रामीण विकास मंत्रालय – लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत बुनियादी ढांचे का विकास

NITI Aayog

नीति आयोग - वन धन के माध्यम से **आकांक्षी जिलों** में आजीविका संवर्धन

CSIR-INDIA

अपने फूलों की खेती मिशन के माध्यम से वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के साथ सहयोग

PMKKKY DISTRICT MINERAL FOUNDATION

डीएमएफ जिलों में जनजातीय आजीविका संवर्धन

अभिसरण भागीदार

प्रधान मंत्री कार्यालय और एलबीएसएनएए - जीआई से संबंधित गतिविधियों को बढ़ावा देने और शुरू करने के लिए सहयोग

विदेश मंत्रालय – ट्राईफेड ने विदेशों में स्थित 100 भारतीय मिशनों में आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर स्थापित करने के लिए मंत्रालय के साथ अभिसरण

कृषि मंत्रालय – ट्राईफेड द्वारा देश भर में 100 किसान उत्पादक संगठन और हनी एफपीओ की स्थापना

संस्कृति मंत्रालय - 8 एएसआई स्थलों पर ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों की स्थापना और लाल किला परिसर में आत्मनिर्भर भारत केंद्र खोलना

वस्त्र मंत्रालय – ट्राईफेड अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना, मेगा क्लस्टर योजना आदि के तहत विभिन्न पहल करने के लिए मंत्रालय के साथ सहयोग कर रहा है

नाबार्ड – जनजातीय विकास हेतु विभिन्न गतिविधियों को शुरू करने के लिए जनजातीय विकास निधि का लाभ उठाने के लिए सहयोग

MoDoNER और भारतीय डाक विभाग - TRIFED इन दोनों विभागों के अभिसरण में पूर्वोत्तर भारत में एक विपणन एवं रसद पहल योजना लागू करेगा

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय जीवन बीमा निगम, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्रालय - हवाई अड्डों और एलआईसी ऑफिसों में विभिन्न ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र खोले गए हैं और कई अन्य स्थानों की पहचान की गई है।

अभिसरण के माध्यम से खुदरा तंत्र का विस्तार

भारतीय जीवन बीमा निगम

3 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र

भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण

8 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

हवाई अड्डों पर 12 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र चालू तथा 13 के लिए आवेदन किया गया है

वस्त्र मंत्रालय

1 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र

पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय

9 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केन्द्रों के लिए स्थलों का चयन

डाक विभाग

2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र

संस्कृति मंत्रालय (क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र)

2 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र

एलबीएसएनएए, मसूरी

1 ट्राइब्स इंडिया बिक्री केंद्र

डिजिटल ट्राईफेड

डिजिटलीकरण और ई-कॉमर्स

ई-कॉमर्स

6900 से अधिक
एसकेयू

14
क्षेत्रीय कार्यालय ईस्टोर्स

50 लाख से अधिक
लाभार्थी

1.32 करोड़
बिक्री

सभी प्रमुख ई-कॉमर्स पोर्टलों पर सूचीबद्ध

Tribes India, Amazon, Paytm, Flipkart, Snapdeal

सोशल मीडिया पर उपस्थिति

Facebook: @tribesindia

Twitter: @tribesindia, @VanDhanSeVikas

YouTube: @tribesindia, @VanDhanSeVikas

Instagram: @tribesindia

Public Financial Management System - PFMS
O/o Controller General of Accounts, Ministry of Finance

व्यय व निधि प्रबंधन के लिए **EAT** मॉड्यूल का **PFMS** के साथ एकीकरण

व्यापक खुदरा सूची प्रबंधन

डिजिटल भुगतान के साथ पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल

डिजिटल निर्देशिका और भंडार

उद्देश्य

- डिजिटल संचार रणनीति में सुधार
- सभी हितधारकों के बीच प्रभावी व निरंतर पहुँच
- वन धन मिशन की हिमायत और पारदर्शिता सुनिश्चित करना

पहुँच

1 लाख
लक्षित आंकड़े

55,765
कुल एकत्रित आंकड़े

डिजिटल व डॉट कॉम की प्रगति

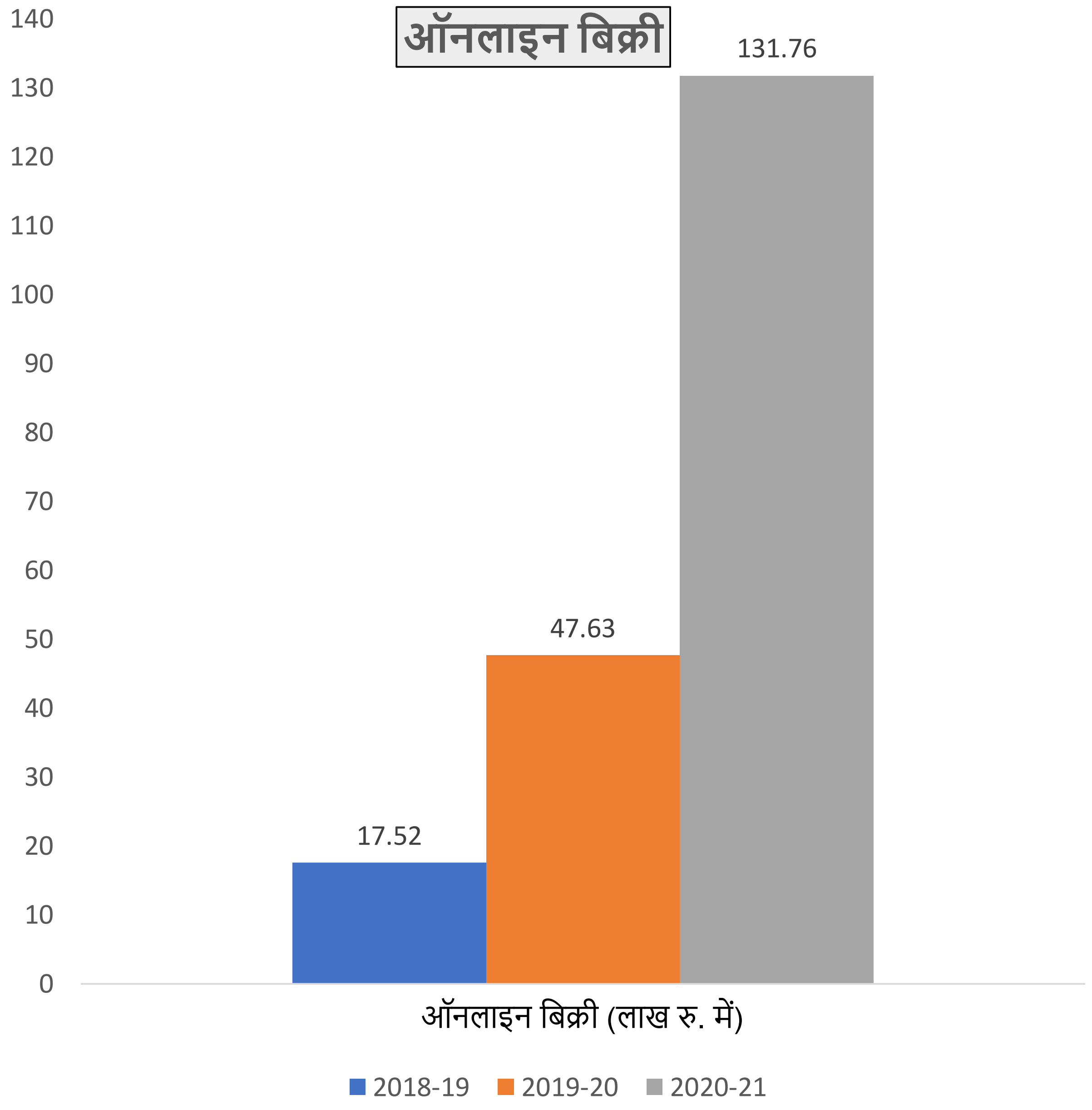

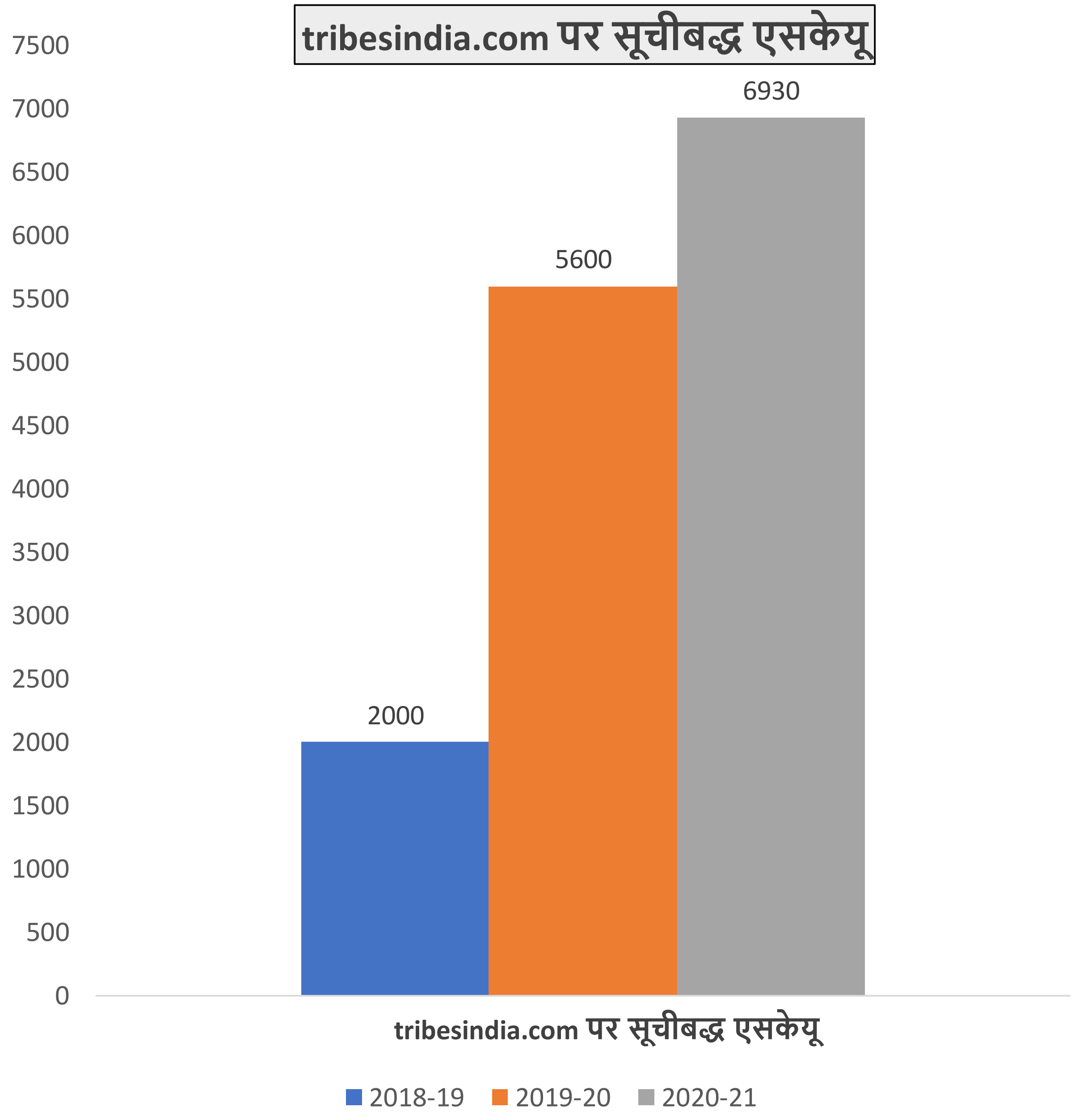

नए डिजिटल प्लेटफॉर्म

1

ट्राइब्सइंडिया ई-मार्केटप्लेस
(लोकार्पण के लिए तिथि : 30 अक्टूबर 2021)

- ✓ पेशेवर पूर्ण विशेषताओं वाला ई-कॉमर्स मार्केटप्लेस
- ✓ उद्योग की सर्वोत्तम प्रथाओं, उपकरणों और विधियों का उपयोग
- ✓ अधिक जुड़ाव और रूपांतरण सुनिश्चित करना, जिससे मजबूत ब्रांडिंग और बिक्री हो
- ✓ कला और कौशल की पहचान के अलावा जनजातीय आपूर्तिकर्ताओं की आय में वृद्धि

2

लघु वनोपजों की न्यूनरम समर्थन मूल्य योजना के लिए प्रॉक्यूरमेंट MIS एप्प
(लोकार्पण के लिए तिथि : 30 अक्टूबर 2021)

- ✓ खरीद एजेंसियों का खाता निर्माण शामिल है
- ✓ सभी खरीद का डेटा एकत्र करना (लाभार्थियों के साथ-साथ मूल्य का भी कवरेज)
- ✓ देश की सभी खरीद एजेंसियों के भौगोलिक प्रतिनिधित्व का नक्शा तैयार करने के लिए
- ✓ हितधारकों का समेकित विवरण डेटा दिखाने के लिए

3

ट्राईफेड क्षेत्रीय कार्यालयों की वेबसाइट
(लोकार्पण के लिए तिथि : 30 अक्टूबर 2021)

- ✓ प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय, उनके कार्यालयों, उनकी विशेषताओं और गतिविधियों के डिजिटल प्रदर्शन के लिए
- ✓ प्रदर्शन और निगरानी के लिए बुनियादी गतिविधियों और प्रदर्शन डेटा का सिंहावलोकन शामिल करने के लिए

वित्त

वित्तीय सुदृढ़ीकरण

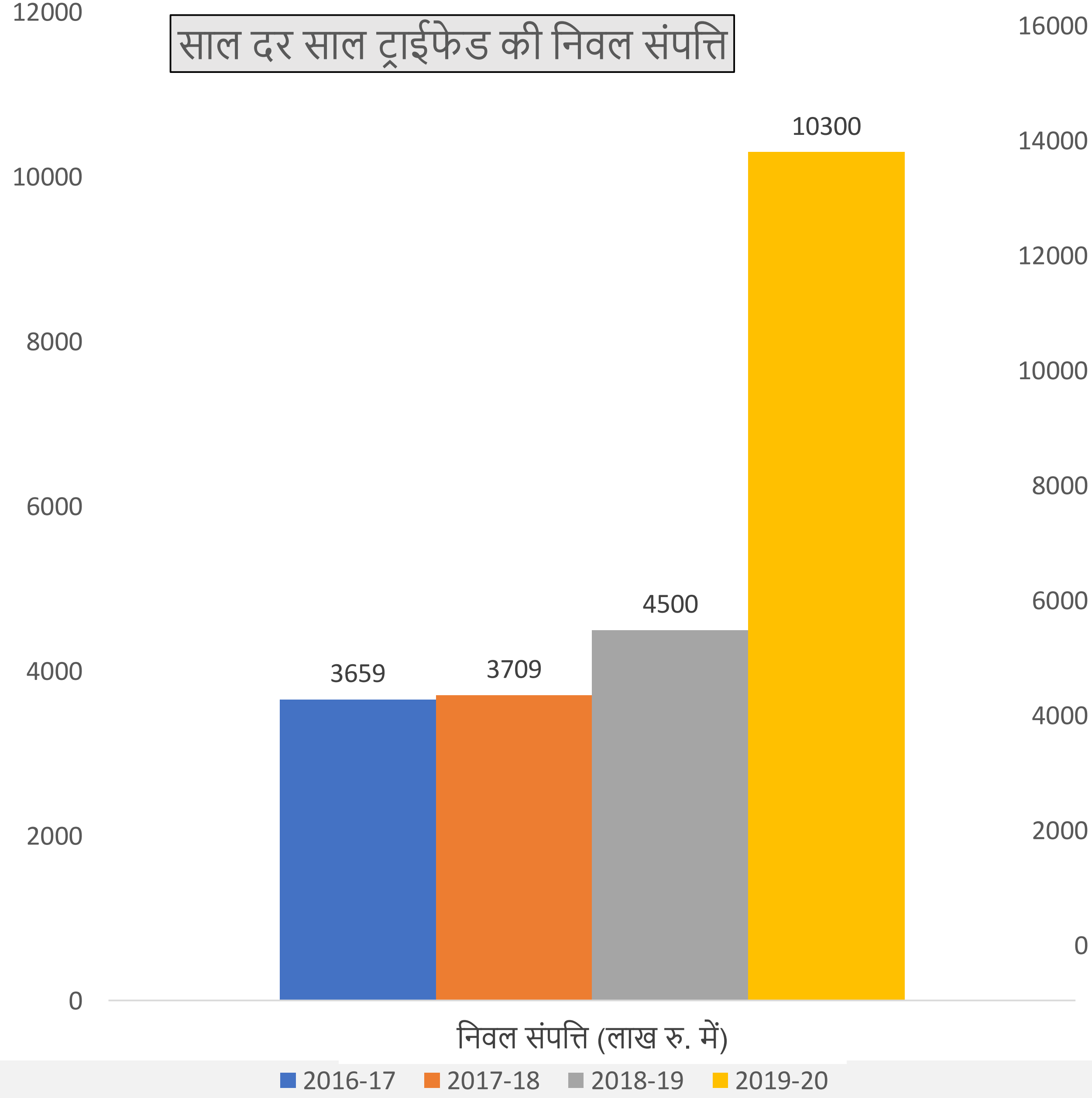

साल दर साल ट्राईफेड की निवल संपत्ति
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
3659
3709
4500
10300
निवल संपत्ति (लाख रु. में)
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20

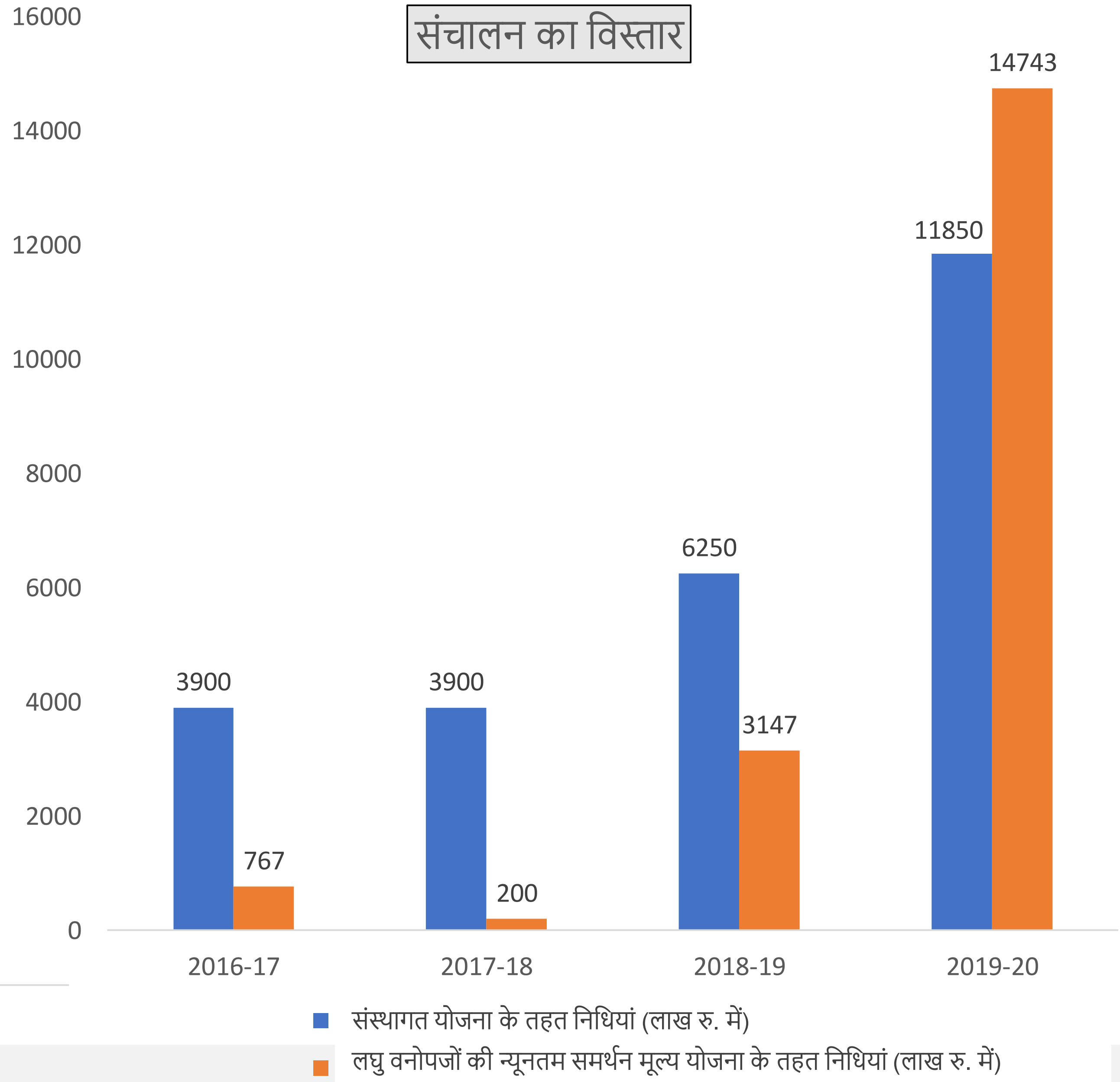

संचालन का विस्तार
16000
14000
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
3900
767
3900
200
6250
3147
11850
14743
2016-17
2017-18
2018-19
2019-20
संस्थागत योजना के तहत निधियां (लाख रु. में)
लघु वनोपजों की न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत निधियां (लाख रु. में)

PMJVM के तहत वित्तीय परिव्यय

योजना	2021-22 (करोड़ रु. में)	2022-23 (करोड़ रु. में)	2023-24 (करोड़ रु. में)	2024-25 (करोड़ रु. में)	2025-26 (करोड़ रु. में)	कुल (करोड़ रु. में)
जनजातीय कार्य मंत्रालय की चालू योजनाएं	305.00	499	312	263.32	232.95	1612.27
अभिसरण से प्राप्त निधियां (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रलाय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय आदि के माध्यम से)	340	356	337	110	110	1253
कुल योग	**645**	**855**	**649**	**373.32**	**342.95**	**2865.27**

योजना के तहत कुल परिव्यय:
रु. 2865.27 करोड़

- ✓ रु. 1612.27 करोड़ व्यय वित्त समिति द्वारा जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत बजट दिया गया है
- ✓ शेष रु. 1253 करोड़ अन्य मंत्रालयों के साथ अभिसरण से प्राप्त किया जाना है

सीएसआर गतिविधियां

ट्राईफेड की सीएसआर गतिविधियां

इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ✓ **परियोजना का नाम:** छत्तीसगढ़ के राजनंदगांव जिले में जनजातीय समुदाय की आजीविका में सुधार लाने के लिए वन धन स्वयं सहायता सहता समूह की स्थापना
- ✓ **बजट परिव्यय: 185 लाख**
- ✓ **1411 लाभार्थियों** का प्रशिक्षण पूरा कर लिया गया है और विकसित उत्पादों को रजवान ब्रांड नाम से बेचा जा रहा है।

राजनंदगांव में लघु वनोपजों का संग्रहण

बड़वानी में प्रशिक्षण

भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

- ✓ **परियोजना का नाम:** मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले में जनजातीय समुदाय का महिलाओं केन्द्रित आजीविका विकास
- ✓ **बजट परिव्यय: 271 लाख**
- ✓ 126 लाभार्थियों के लिए 6 वन धन स्वयं सहायता समूहों की स्थापना (बाग प्रिंट, माहेश्वरी टेक्सटाइल व चंदेरी टेक्सटाइल प्रत्येक के लिए 2)। एक राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता इन लाभार्थियों को प्रशिक्षण दे रहा है।

कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

- ✓ **परियोजना का नाम:** वन धन स्वयं सहायता समूहों की स्थापना के माध्यम से आजीविका विकास
- ✓ **बजट परिव्यय: 20 लाख**

कार्मिक व प्रशासन

मानव संसाधन विकास

वास्तविक संख्या बनाम स्वीकृत संख्या

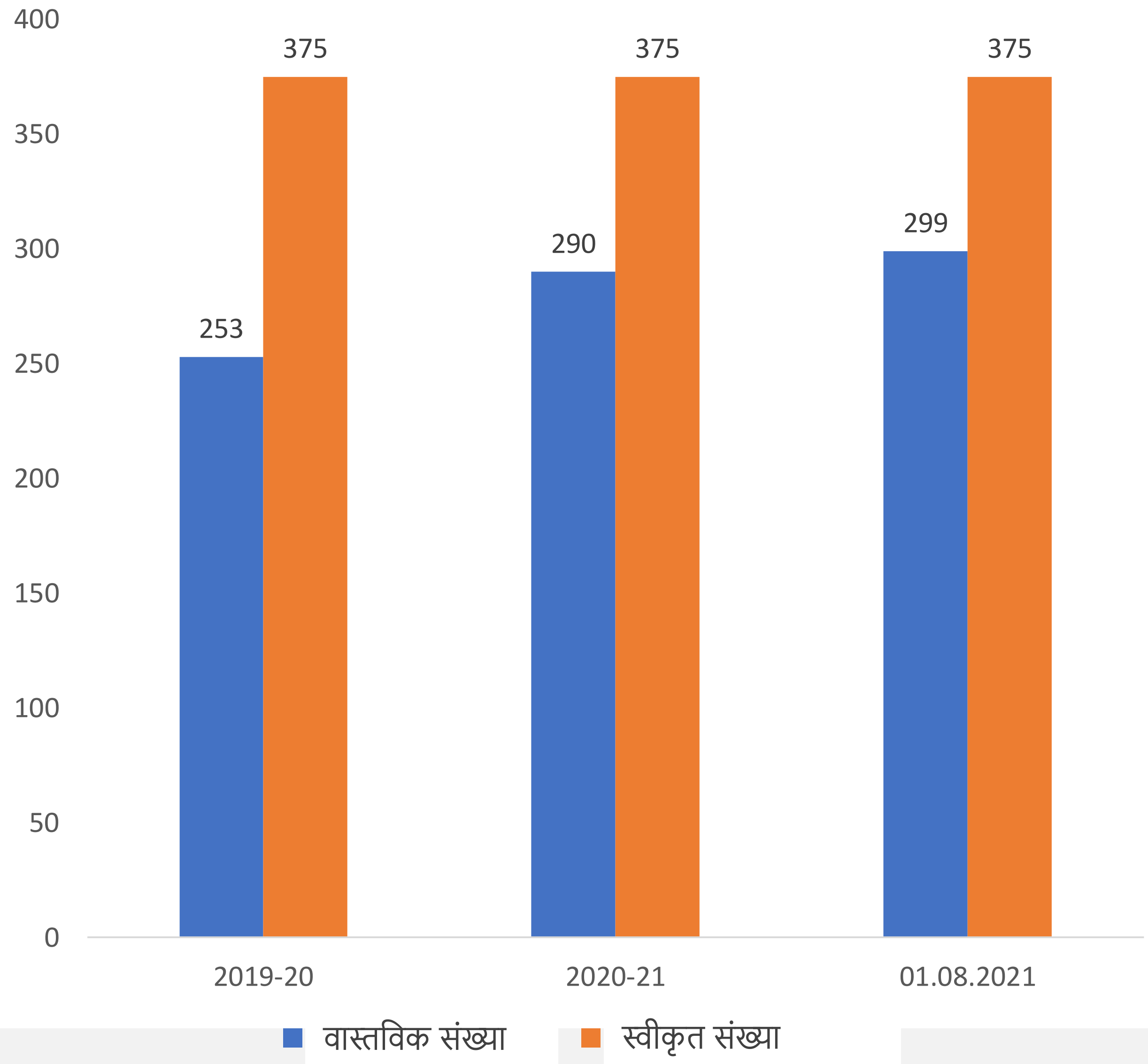

ट्राईफेड
TRIFED

एडसिल
EdCIL
Education • Innovation • Transformation

- ✓ ट्राईफेड के उद्देश्यों की समीक्षा की गई और संगठन को प्रासंगिक बनाने और जनजातीय कल्याण से जुड़ने के लिए पुनर्परिभाषित किया गया।
- ✓ कर्मचारियों को ट्राईफेड की दूरदर्शिता और मिशन के साथ खुद को फिर से समर्पित करने और पुनर्परिभाषित उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में काम करने के लिए प्रेरित किया गया।
- ✓ साथ ही, **मानव संसाधन विकास मंत्रालय के तहत EdCIL** के माध्यम से भर्ती के लिए **90** से अधिक संसाधनों की पहचान की गई

कुछ लघु अंश

डिजिटल तथा डॉट कॉम सेवाओं का प्रारम्भ

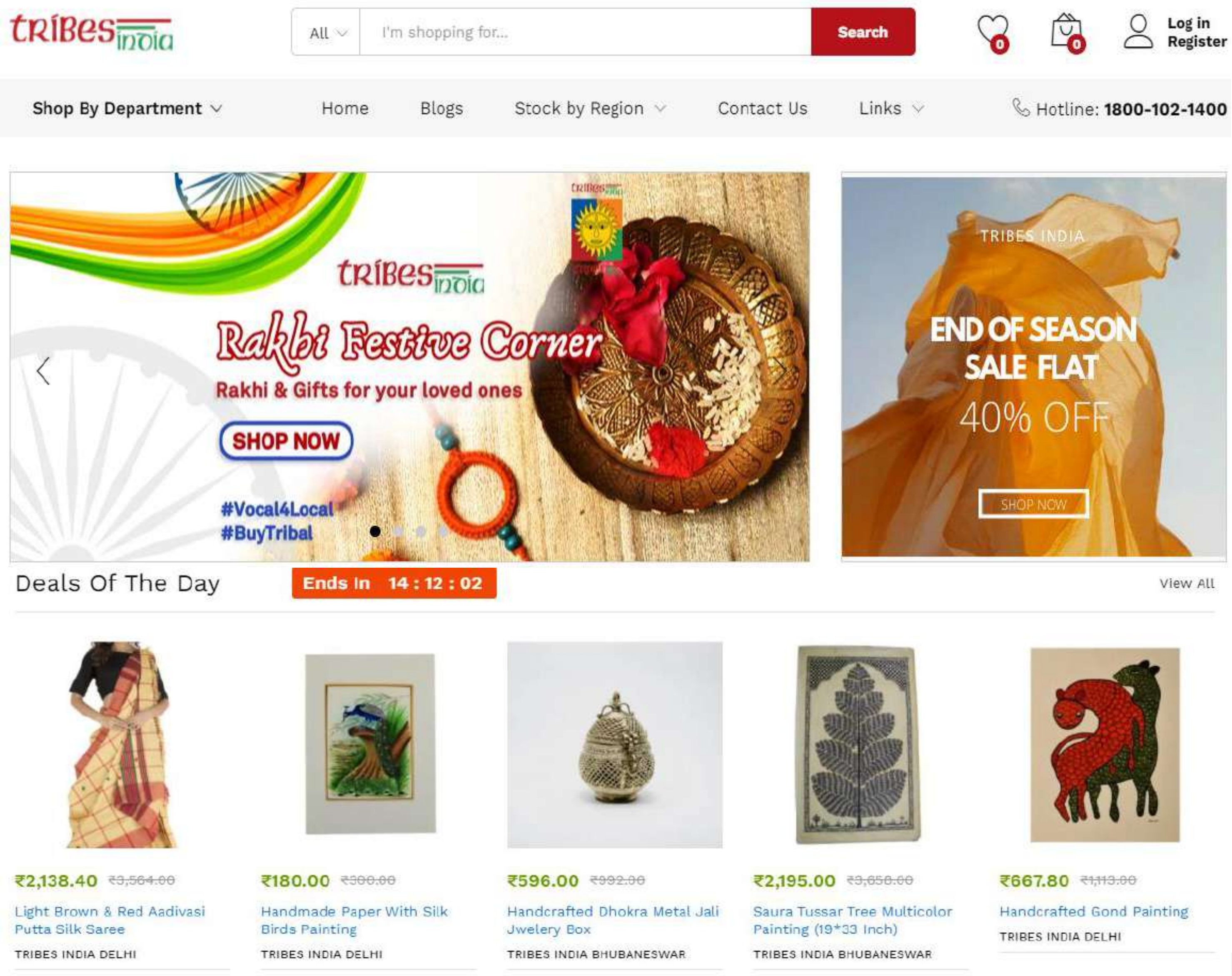

वन धन योजना की अवधारणा

वीडीवीकेसी सदस्यों द्वारा मूल्य संवर्धन - गिलोय (शाहपुरा महाराष्ट्र)

वीडीवीकेसी सदस्यों द्वारा मूल्यवर्धन – जोहा चावल का प्रसंस्करण व पैकेजिंग

अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर न्यूयार्क में ट्राइब्स इंडिया की झलकियां

आदि महोत्सव

आदि महोत्सव

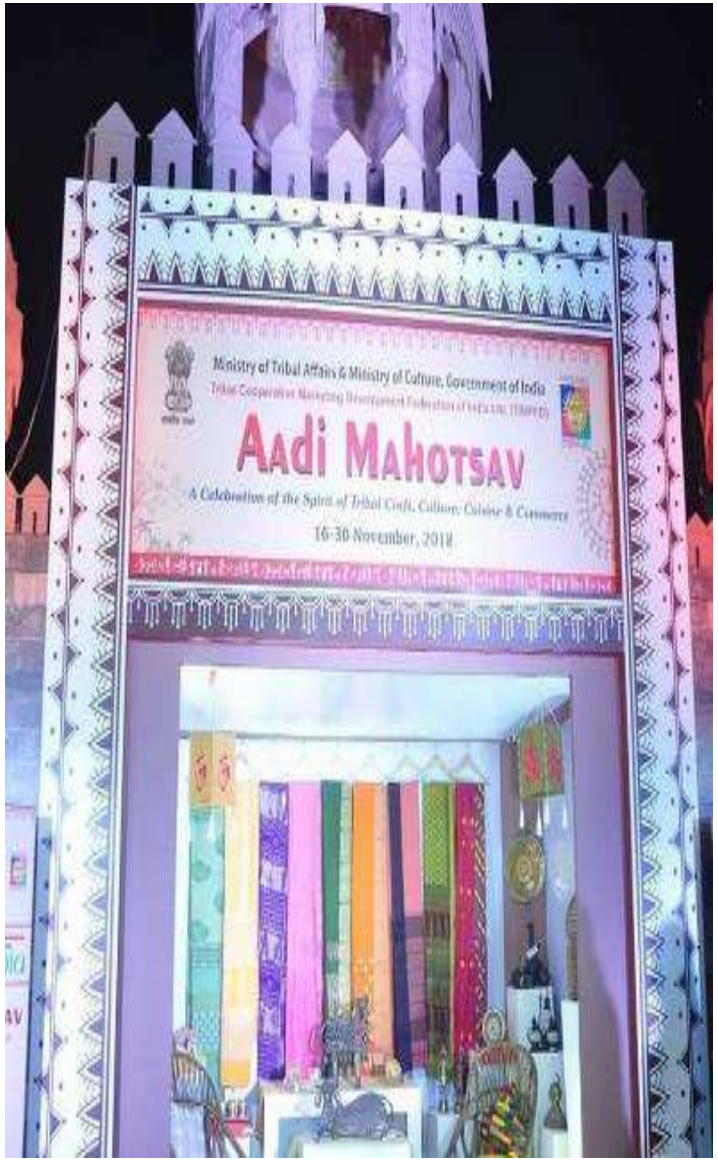
Ministry of Tribal Affairs & Ministry of Culture, Government of India
Aadi Mahotsav
16-30 November, 2018

आदि महोत्सव
DEEPAK KHANDEKAR

पुरस्कार रात्रि

ट्राईफेड का नया मुख्यालय

जनजातीय कार्य मंत्रालय
भारत सरकार

ट्राईफेड
TRIFED

धन्यवाद